राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
YouTube Linked in
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023 (Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण शनिवार,10अक्टूबर2020 वर्ष-3, अंक-254 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बड़ी राहतः

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही कोरोना संक्रमितों की कमी

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटो के दौरान 3249 नये संक्रमित मिले जबकि 4424 मरीज पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को यहां बताया कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के केस लगातार कम हो रहे है, ऐसे में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 3,249 नये मामले आये हैं जबकि 4,424 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल 3,83,086 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राज्य में गुरूवार को एक दिन में कुल 1,73,336 सैम्पल की जांच की गयी। राज्य में अब तक कुल 1,15,49,475 सैम्पल की जांच की गई है। प्रसाद ने बताया कि राज्य में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 88.95 प्रतिशत है। प्रदेश में 41,287 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। होम आइसोलेशन में 19,430 लोग हैं। अब तक कुल 2,36,000 लोग होम आइसोलेशन में है जिसमें से 2,16,656 लोगों होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर लिये है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस टीम दिवस के माध्यम से 1,35,390 क्षेत्रों में 4,09,593 टीम दिवस के माध्यम से 2,65,84,047 घरों के 13,14,27,744 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 3,112 लोग इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी पोटर्ल के माध्यम से पिछले 24 घन्टे में 2090 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। अब तक कुल 1,27,557 लोगों ने चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया है। प्रदेश में पूल टेस्ट के तहत कल 3783 पूल की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आर0टी0पी0सी0आर0, एन्टीजन व टू्नेट के माध्यम से जांच हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जांच और इलाज निशुल्क किया जा रहा है।

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस

नेशनल डेस्कः अनलॉक 5 में जहां तमाम आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, वहीं भारतीय रेल सेवा भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। विशेष ट्रेनों के साथ-साथ भारतीय रेल ने धार्मिक स्थलों से अपने रेल सेवा भी बहाल करने का फैसला किया है। इस बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द बहाल की जाएगी। सिंह ने बताया कि नवरात्रि से पहले जम्मू-कश्मीर में कटरा के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा की गई। सिंह ने ट्वीट किया, 'रेल मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली-कटरा (वैष्णो देवी) वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बहाल करने को लेकर चर्चा की। नवरात्रि में पवित्र स्थल जाने की योजना बना रहे देशभर के श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी आश्वस्त करने वाली होगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण मार्च में रेल सेवाएं बाधित हो गई थीं, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है।

मणिपुर, अरुणाचल में भूकंप के हल्के झटके, कोई नुकसान नहीं

इम्फाल/ईटानगर। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई, हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को भूकंप कई सेकंड तक रहा, जिससे घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मॉलजी के आंकड़ों के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके पूर्वी मणिपुर के कामजोंग जिले में तड़के 3.12 बजे अनुभव किए गए, इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा। रिक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता का एक और भूकंप, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सुबह 8.21 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। मणिपुर में शुक्रवार को आया भूकंप 48 घंटे में दूसरा भूकंप है। बुधवार को पूर्वी मणिपुर के उखरूल जिले में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

राजस्थान में पुजारी की हत्याः भाजपा ने साधा निशाना, कहा- अब गहलोत से इस्तीफा मांगें राहुल गांधी

नई दिल्लीः राजस्थान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनकी सरकार को ''सुधारने'' की कवायद करनी चाहिए। राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में एक पुजारी को कथित तौर पर आग लगा दी गयी। इसके बाद एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ''बेहद ही गंभीर'' मामला बताते हुए राज्य सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए।'' केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज पुजारी की जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले ही राज्य के बहरोड़ पुलिस थाने पर एके-47 हमले में अपराधियों को छुड़ा ले जाने की घटना हुई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है।'' राजस्थान में हाल के दिनों में हुई बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, ''राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी 'भारत दर्शन' की बजाए राजस्थान के जिले-जिले में जाना चाहिए।

स्वामित्व योजना के तहत 'संपत्ति पत्र' देंगे पीएम मोदी

नई दिल्लीः (एजेंसी)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को 'स्वामित्व' योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर उपलब्ध कराये जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। बयान के अनुसार महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिये कुछ राशि लिये जाने की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा। पीएमओ के बयान के अनुसार यह पहली बार है कि लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लाभ के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरूआत की थी। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। बयान के अनुसार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से चार साल (2020-24) में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांव आएंगे।

स्वदेशी रूप से विकसित विकिरण-रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत ने शुक्रवार को स्वदेशी विकिरण-रोधी (एंटी-रेडिएशन) मिसाइल (रुद्रम-1) का सफल परीक्षण किया। रुद्रम मिसाइल किसी भी सिग्नल अथवा रेडिएशन को पकड़ सकती है और रडार पर लाकर इसे नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायु सेना के लिए पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य हितधारकों की सराहना की। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा, नई पीढ़ी की एंटी-रेडिएशन मिसाइल (रुद्रम) को ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर स्थित एक विकिरण लक्ष्य पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल को सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया है। मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है, जिसमें प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर अलग-अलग रेंज की क्षमता है। डीआरडीओ ने कहा, इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ आईएनएस-जीपीएस नेविगेशन है। रुद्रम ने रेडिएशन लक्ष्य को पिन प्वाइंट सटीकता से मारा। पैसिव होमिंग हेड एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्य का पता लगाने, वर्गीकृत करने और लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम है। मिसाइल बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से प्रभावी तरीके से दुश्मन के वायु रक्षा को रोकने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक शक्तिशाली हथियार है। इसके साथ ही, देश ने दुश्मन रडार, संचार साइटों और अन्य आरएफ उत्सर्जक लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए लंबी दूरी की हवा में लॉन्च की गई एंटी-रेडिएशन मिसाइल विकसित करने के लिए स्वदेशी क्षमता स्थापित कर ली है। इस महीने की शुरूआत में, डीआरडीओ ने पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया था, जिससे नौसैनिक युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई है।

पैसों की कमी का बहाने बनाने वाला कैसा नेता - शिवराज

भोपाल।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की सरकार द्वारा पैसे की कमी बताए जाने के बयानों पर तंज कसा और कहा कि जो नेता पैसों की कमी का बहाना बनाए, वह कैसा नेता। मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को सुवासरा, हाटपिपल्या के मंडल सम्मेलनों में हिस्सा लिया और कहा कि, कांग्रेस सरकार के समय जब भी कोई विधायक, मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं हैं। लेकिन मामा कहता है विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो पैसे की कमी का बहाना लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, वो नेता कैसा? नेता तो वही है जो आड़े वक्त पर लोगों के काम आए। जो मुसीबतों के बीच से रास्ता निकाल ले। मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि, कमलनाथ सरकार पूरे समय पैसे की कमी का रोना रोती रही, लेकिन हमने कोरोना संकट में भी इसके लिए व्यवस्था की। यह सही बात है कि आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हमने उसके बीच से रास्ता निकाला। कोरोना काल में भी हमने गरीबों, मजदूरों के खाते में पैसे डाले। एक लाख 78 हजार हितग्राहियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा के पैसे डाले। 14 सौ करोड़ रुपए पेंशन के डाले। बच्चों की स्कॉलरशिप के 540 करोड़ रुपये दिए, मध्यान्ह भोजन के पैसे दिये और रसोइयों के खातों में दो-दो हजार रुपये डाले। हर एक व्यक्ति को भोजन मिले इसकी व्यवस्था की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर भी चौहान ने चुटकी ली, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या पाप किया, जो सरकार गिराई।

नए यूपी में माफियाओं को संरक्षण नहीं, केवल मानमर्दन : मुख्यमंत्री

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी ने वह दौर भी देखा है जब अपराधी-माफिया राजनीतिक दलों की नीतियां तय करते थे। सत्ता इन्हें सिर-आंखों पर रखती थी, जिसकी बदौलत यह लोग खूब फले-फूले। गरीबों की जमीनों पर काबिज कर महल खड़े कर लिए। पर अब यह सब नहीं चलेगा। यह नया यूपी है, जो अपराधियों का मानमर्दन करता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर मल्हनी (जौनपुर) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर वहां के बूथ, मंडल और सेक्टर के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, विकास का कोई विकल्प नहीं। कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी 87 लाख पात्रों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को एडवांस पेंशन, चार करोड़ घरों को बिजली, 41 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन, गरीबों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय, प्रदेश की 24 करोड़ से अधिक जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहले चरण में हर मंडल में मेडिकल कॉलेज, विश्वस्तरीय बुनियादी संरचना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्स्प्रेस-वे का निर्माण, देश और दुनिया को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए जेवर, कुशीनगर, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के साथ अन्य जगहों पर एयरपोर्ट का निर्माण इसका सबूत है। योगी ने कहा कि, कुछ लोग जिनकी सोच में ही विकास नहीं है। जिनकी सोच जाति, मजहब, धर्म और क्षेत्र तक सीमित है। जो पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं। अराजकता और भ्रष्टाचार जिनकी पहचान है। जिनके जमाने में विकास के 90 फीसदी पैसे का बंदरबाट हो जाता था, उनको बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शीता के साथ हो रहे विकास के कार्य और गरीबों की खुशहाली रास नहीं आ रही है। लिहाजा वह समाज को बांटने का वही पुराना हथकंडा अपना रहे हैं। पर अब ऐसे लोगों की दाल गलने वाली नहीं। जनता सब जान चुकी है। लगातार उनको बता भी रही है। उपचुनाव में भी बताएगी।

रामविलास पासवान को PM मोदी की श्रद्धांजलि, बोले- दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं...दोस्त खो दिया

नेशनल डेस्कः देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को शुक्रवार अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली उनके घर जनपथ लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग को भी सांत्वना दी। चिराग पासवान की इस दौरान आंखें नम थी। वहीं पीएम मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जब गुरुवार को रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं, मैंने एक दोस्त और मूल्यवान सहयोगी को खो दिया है। बता दें कि दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री का पार्थिव शरीर 2 बजे पटना लाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को पटना लोजपा कार्यालय से विधानसभा ले जाया जाएगा। शनिवार यानी 10 अक्तूबर को रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पटना में ही होगा। वहीं दिवंगत केंद्रीय मंत्री के सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिता के निधन की सूचना साझा करते हुए ट्वीट किया, ''पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। **Miss You PapaÐ''** लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान कई सप्ताह से यहां के एक अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। फार्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी बयान के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पासवान के स्वास्थ्य में गिरावट आई और गुरुवार को शाम 6 बजकर पांच मिनट (06¬05 शाम) पर उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवादी आंदोलन के स्तंभों में से एक पासवान बाद के दिनों में बिहार के प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे और जल्दी ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशेष जगह बना ली।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

बचाव का अभियान

अनलॉक होते देश में फैलते कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जितने भी किए जाएं, कम होंगे। हल्की सर्दी और उसके साथ ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ने लगी है। ऐसे में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जागरूकता अभियान की शुरुआत स्वागतयोग्य है। कोरोना से निपटने और बचने के लिए जरूरी है, हम पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहें। जीविका के लिए घर से निकल रहे लोगों के मन में डर भले कम हुआ हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ, बल्कि पहले की तुलना में बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस जरूरी अभियान को बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी। सरकार चाहती है कि यह अभियान जन-आंदोलन की तरह चले। इसमें जनता की पूरी भागीदारी हो। मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और हाथ धोने के मोर्चे पर कोई कोताही न बरते। यह कोरोना से सबसे सस्ता और कारगर बचाव है।

विशेषज्ञ भी अनेक बार दोहरा चुके हैं कि किसी दवा या कोरोना की वैक्सीन के अभाव में मास्क, शारीरिक दूरी और हाथ धोना सुरक्षित रहने के प्रभावी हथियार हैं। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल, संस्कृति, फिल्म उद्योग, रेलवे इत्यादि के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने और सतर्क करने का काम किया जाना है। आज वाकई कोविड के खिलाफ संकल्प लेने और दोहराने की जरूरत है। सभी केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रालयों और विभागों को इस अभियान के तहत पूरी सतर्कता के साथ काम करना होगा। सरकार के स्तर पर दिग्गज नेताओं और अधिकारियों को भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पूरे देश को प्रेरित करना होगा। यह देखना दुखद है कि बड़े-बड़े नेता संक्रमण की चपेट में आए हैं। खास तौर पर पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के जो आंकड़े मुंबई से आ रहे हैं, वे निराश करते हैं। लोगों को पूर्णत- सजग करने के लिए सरकारी विभागों को अपने यहां बचाव के इंतजामों का काया-कल्प करना होगा। भारत में कोरोना के आंकड़ों को देख लेना चाहिए और इस धारणा से निकलना चाहिए कि मुझे कोरोना नहीं होगा। कोरोना का मजाक उड़ा रहे कई लोग संक्रमण के बाद अब दूसरों को समझाते थक नहीं रहे हैं। जो इसका दर्द झेल चुके हैं, उन्हें आगे रखते हुए सरकार को यह अभियान चलाना चाहिए। ऐसे लोग, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। सरकार ने उचित ही अब तमाम औद्योगिक और कारोबारी संगठनों को इससे जोड़ने का फैसला किया है। घर, दफ्तर से अस्पताल तक कोरोना के खिलाफ जो भी ढिलाई आई है, उसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

अब समय आ गया है, जब कोरोना के खिलाफ अच्छा काम करने वालों का सम्मान भी किया जाए। ऐसे संस्थानों को सम्मानित किया जाए, जिन्होंने सतर्कता और जागरूकता के लिए अपना तन-मन-धन लगाया हो। विभिन्न संस्थानों को भी खुद से जुड़े सेवाभावियों की पीठ थपथपानी चाहिए। कुल मिलाकर, आभार प्रदर्शन इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। कोरोना से बचाव का संदेश गली-गली तक हरसंभव माध्यम से पहुंचाना चाहिए। ऐसे व्यापक अभियान की जरूरत आज भारत में सर्वाधिक है। हमारे यहां न केवल कोरोना बढ़ रहा है, बल्कि त्योहार भी आ रहे हैं। बेशक, यह अभियान हमारे त्योहारों का हिस्सा बन जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं।

सांसें बचाने का वक्त

दूषण का मसला दिल्ली-एनसीआर में लगातार गंभीर होता जा रहा है। लॉकड़ाउन के दौरान हालांकि न केवल वायु प्रदूषण में भारी कमी देखी गई, वरन नदियां भी शुद्ध हो गइफा लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण फिर तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण बढ़ने के मामले पराली जलाने से तो कुछ फीसद निर्माण कायोफमें बढ़ोतरी के कारण दर्ज किए गए हैं। नतीजतन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ (सीपीसीबी) को आगे आना पड़ा है। बोर्ड़ ने राजधानी दिल्ली में निर्माण एवं निर्माण को गिराने संबंधी गतिविधियां और खुले में कूड़ा डाले जाने को वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होने का उल्लेख करते हुए इन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। स्वाभाविक है कि सर्दियों में वायु प्रदूषण भयावह स्थिति में पहुंच जाता है। यही वजह है कि सीपीसीबी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरे किए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध कार्य सूचीबद्ध किए। सीपीसीबी का यह मानना है कि अगर सख्त नियम नहीं बनाए गए और उनका कायदे से पालन नहीं कराया गया तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे। वैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए कुछ कार्य पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी और किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को तीन डंपिंग स्थलों भलस्वाग गाजीपुर और ओखला में मिश्रित ठोस अपशिष्ट डाले जाने पर जल्द कदम उठाने को कहा है। आने वाले दिनों में खतरा ज्यादा इसलिए है कि दीपावली में आतिशबाजी होगी। गौरतलब है कि एक छोटा पटाखा 10 लीटर और बड़ा पटाखा 100 लीटर तक ऑक्सीजन खत्म कर देता है। जरूरी है कि जनता खुद से पटाखों पर रोक लगाए। ऐसे कदम उठाकर ही गंभीर बीमारियों को हराया जा सकता है। आने वाले महीनों में निश्चित तौर पर ज्यादा सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार के साथ ही जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एक महझ्रवपूर्ण बात यह भी कि अब सिर्फ महानगरों की स्थिति पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटे शहरों मसलन राज्यों की राजधानी और टू टीयर के शहर भी प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बेशकग सीपीसीबी ज्यादा सक्रिय है लेकिन बाकी संस्थाओं को भी आगे आकर इस लड़ाई को फतह करने का बीड़ा उठाना होगा। यह जंग हमें हर हाल में जीतनी होगी क्योंकि यह सांसें बचाने का वक्त है।

परिधि/विशाल तिवारी

धोखे की दुकान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में 24 स्वयंभू गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की है जिसमें इन्हें फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह एक अच्छी खबर है पर इस संदर्भ में कुछ समान्य से सवाल भी उठते हैं। पहलाग कोई विश्वविद्यालय रेहड़ी-पटरी की दुकान नहीं, जिसे जब कोई चाहे लगा ले। आखिर, ये अस्तित्व में कैसे आए? दूसराग अभी भी यूजीसी सिर्फ इन्हें फर्जी करार देने, छात्रों को आगाह करने की कार्रवाई तक ही क्यों सीमित है? जबकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही ऐसी धोखे की दुकानों को संचालित करने पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सूचनात्मक या प्रतीकात्मक कार्रवाई से इनके हौसले पस्त नहीं होने वाले। यूजीसी पहले भी फर्जी ड़िग्री बांट रही ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। इसके बावजूद फर्जी संस्थान पनपना व्यवस्था कीआश्वस्ति या शह की तरफ इशारा करते हैं। यह काफी कुछ सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण जैसा है, जो प्रशासन की आंख के सामने उसकी शह से होता है। बाद में कभी सवाल उठने पर रफा-दफा करने का प्रयास किया जाता है।

दरअसल, एक और बिंदु, जो चौंकाता है, इन 24 में से 7 का दिल्ली से होना है यानी एक प्रकार से यूजीसी की नाक के नीचे का मामला है। इन फर्जी विश्वविद्यालयों के संचालकों के आत्मविश्वास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आज जब ड़िग्रियों की महत्ता का अंदाजा सभी को हैग तो ऐसे में किसी को ड़िग्री पूरी करने के बाद यह पता चले कि उसकी यूजीसी से मान्यता नहीं है, तो उसके लिए पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात हो जाती है। एक छात्र के आत्मबल को तोड़ने जैसा काम है यह। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि फर्जी करार दिए गए इन संस्थानों के समूचे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर इनका सहयोग देने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को एक कड़ा संदेश जाएगा। हां, यह संदेश दो तरफा भी होगा। चूंकि इस तरह के फर्जी संस्थान की जगह तभी बनती है जब लोग बाग बिना मेहनत के अदद ड़िग्री की तलाश में रहते हैं। देश में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो पैसे देकर ड़िग्री खरीदने को तत्पर रहते हैं। बहरहाल, सबसे महझ्रवपूर्ण कड़ी जागरूक लोग हैं, जिन्हें ऐसे फर्जी संस्थानों के संज्ञान में आते ही उचित स्तर पर उन्हें उजागर करना चाहिए।

कम से कम पूजा के सामान हों देशी

रितु कुमार

वह 2017 के फरवरी महीने की एक सर्द सुबह थी। मैं पेरिस में थी। हम एवेन्यू मोंटेन्यू गली से गुजर रहे थे, जो एफिल टावर को चैंप एलिसिस से जोड़ती है। यह फैशन दुनिया की सबसे ग्लैमरस सड़क है। इसे यूरोप के हाउते कॉउचर (इस डिजाइन में मशीन से सिलाई नहीं की जाती) डिजाइनरों का घर भी कहा जाता है। मुझे वहां यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एलवीएमएच स्टोर में दाखिल होने के लिए चीनी ग्राहक कतार में इंतजार कर रहे हैं। जब मैं स्टोर में प्रवेश करने वाली थी, तभी दो चीनी महिलाएं मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे लुई विटॉन से किसी भी कीमत की दो हैंडबैग खरीदने की गुजारिश की। दरअसल, स्टोर में ब्रिकी के लिए कोटा सिस्टम लागू था और चूंकि उन दोनों को कोटा के तहत रियायत मिल चुकी थी, इसलिए उन्हें मेरी मदद की दरकार थी।

इस साल फरवरी में मैं फिर से उसी गली में थी। अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जिसकी तस्दीक धनाढ्य ग्राहकों की कमी से हो रही थी। वहां एकमात्र खरीदार चीनी थे, और खरीद पर कोटा प्रणाली के दिन कमोबेश लद चुके थे। मगर मामला सिर्फ उपभोग का नहीं है। दरअसल, चीनी अब फैशन की दुनिया में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं, क्योंकि वे संसार के लगभग सभी लग्जरी कपड़ों व सामान का निर्माण और आपूर्ति करते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी है और बाजार से चीनी सामान गायब होने लगे हैं।

हालांकि, भारतीय बाजार पर चीन की नजर कायम है और वह बहुत मामूली कीमत पर लोकप्रिय भारतीय शिल्प के नकली-उत्पाद बेचना चाहता है। चीनी जब किसी बाजार में उतरते हैं, तो वे लागत पर ध्यान नहीं देते। उनके उत्पादों की कीमतें उनकी राजनीतिक नीति से तय की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के फैशन और विवाह कारोबार में उतरने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के मूल्यों और उनकी आदतों का अध्ययन करके चीनी जल्द ही कलेक्शन जुटाने में माहिर रहे हैं। दुर्भाग्य से भारतीय हस्त शिल्प के मामले में चीन मशीन-निर्मित विकल्पों से उत्पादन करना चाहता है। वह यहां के शिल्प कौशल की मशीनी नकल कर रहा है, जबकि आज भी भारत के 1.6 करोड़ शिल्पकार रोजाना अपने हाथों से यह काम कर रहे हैं।

> हमें चीन से धार्मिक वस्तुओं के आयात पर सख्त प्रतिबंध लगाकर अपने कुम्हारों, शिल्पकारों और शिल्प की रक्षा करनी चाहिए।

जाहिर है, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खासकर यह देखते हुए कि भारतीय शिल्पकार कोविड-19 संकट के कारण पहले से ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए कि भारतीय बाजार आज क्यों चीन के नकल वाले उत्पादों से भरे पड़े हैं, जबकि वे सस्ते कपड़ों पर बनाए जाते हैं? अब तो इस फेहरिस्त में कई अन्य बड़े नाम भी हैं, जैसे बनारसी और चंदेरी साड़ियां; सिंथेटिक पर छापी जा रही राजस्थानी बंधेज कलाकारी; गुजरात और कच्छ की मिरर वर्क कशीदाकारी; कांथा, सुजनी, फुलकारी और लखनऊ कढ़ाई, जो चीन में मशीन द्वारा सिंथेटिक पर बनाई जा रही हैं; बंजारा बैग और कोल्हापुरी चप्पल, जो अब ज्यादातर झिंजियांग से आयात किए जाते हैं; मंगोलियाई ऊन से बनी नकली कश्मीरी शॉल, जिस पर पश्मीना का टैग लगाया जाता है इत्यादि। चीन से आयातित इन उत्पादों में से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो अब यहां के छोटे-बड़े बाजार में भी उपलब्ध नहीं हो। इससे बेशक स्थानीय स्तर पर रोजगार-सृजन में मदद मिली है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसके बदले में वे स्थापित शिल्प क्षेत्रों से काम छीन भी रहे हैं।

भारत एकमात्र देश है, जिसने अपनी फैशन पहचान को छोड़ा नहीं, बल्कि उसका संरक्षण किया है। इसे नया रूप दिया गया है, जो पारंपरिक तिमिर चित्र, शिल्प और कपड़ा-निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। देखा जाए, तो सही मायने में मेक इन इंडिया उत्पाद। यह एक चमत्कार है, और पहेली भी, जब हम इसकी तुलना जापान और मैक्सिको जैसे देशों से करते हैं। वहां ऑर्गेनिक कपड़े अब म्यूजियम की शान बन गए हैं और देश पेरिस की रैंप की नकल करने लगे हैं।

जिन-जिन लोगों से मैंने बात की, उनमें से अधिकांश ने परेशान करने वाला यही रुझान बताया कि भारतीय त्योहारों के समय बाजार में चीन की घुसपैठ बढ़ जाती है। बेशक वहां से रंग-बिरंगी झालरें आयात की जा सकती हैं, हालांकि इसे बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसे आसानी से अपने यहां तैयार किया जा सकता है, मगर अपने यहां दीये; गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती की मूर्तियां; राधा और कृष्ण के सेट भी वहीं से आयात किए जाते हैं, जबकि वह हमारी धार्मिक प्राथमिकताओं को लेकर कतई संवेदनशील नहीं है। इनके आयात की समीक्षा की जानी चाहिए। अपने यहां ये लगभग पवित्रता से बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और पुआल से बनाई जाने वाली काया हाथ से तैयार की जाती है। ये उत्पाद आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा त्योहार के मौसम में ही बनाए जाते हैं। वैसे भी, अपने यहां पूजा के लिए मिट्टी की वस्तुएं बनाने का अनुष्ठान गहरा व ऐतिहासिक है। इतना ही नहीं, ये प्राकृतिक तरीके से नष्ट भी किए जा सकते हैं और इनका पुनर्निर्माण भी संभव है। इसीलिए हमें धार्मिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाकर अपने कुम्हारों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी आयातित वस्तुओं पर प्लास्टिक की परत होती है और पूजा के बाद जब इनका विसर्जन किया जाता है, तो ये नदियों को प्रदूषित करती हैं। कोविड-19 के कारण वैसे ही कुम्हारों को इस साल ऑर्डर कम मिले हैं, ऐसे में, चीन से दिवाली से जुड़े उत्पादों को आयात करना समझदारी नहीं है। जब हम 'आत्मनिर्भर भारत' की वकालत करते हैं, तो देश को गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात की समीक्षा करनी ही चाहिए। पहले से तनावग्रस्त शिल्प क्षेत्र को आज संरक्षण की जरूरत है, शिंजियांग और शिआमेन से प्रतिस्पर्द्धा करने की नहीं, जहां डिजिटल मशीनों से नकली कढ़ाई करके बिना किसी कीमत के नकल तैयार कर ली जाती है। त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले चीन से होने वाले इन आयात पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए, ताकि पहले से भयंकर मुश्किलें झेल रहे हमारे शिल्पकारों की रक्षा हो सके। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)

चर्चित चेहरा

पहाड़ काट जलधारा लायी अलबेली जल सहेली

अरुण नैथानी

जीवन के लिये पानी के क्या मायने होते हैं, सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड की महिलाओं से बेहतर यह कौन जान सकता है। होश संभालते ही बेटियां हैंडपंपों पर तड़के से ही कतार लगाकर खड़ी हो जाती हैं। सिर पर सूरज आने तक यही पानी ढोने का क्रम चलता है। कई बच्चियों का स्कूल पानी भरने की जिम्मेदारी की भेंट चढ़ जाता है। पानी लेने को नंबर लगाने को लेकर विवाद भी इसी जद्दोजहद का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंगरोठा गांव की महिलाओं ने गर्मियों में पैदा होने वाले भीषण संकट को हमेशा-हमेशा के लिये खत्म करने का संकल्प लिया। इस लक्ष्य को एक पहाड़ काटकर हकीकत में बदला। महिलाओं का नेतृत्व करने वाली 19 साल की बबीता आजकल सुर्खियों की सरताज है। उसके प्रयासों से भावी पीढ़ियों का जल संकट खत्म हुआ है।

सही मायनो में सूखे बुंदेलखंड में पानी के स्थायी समाधान के लिये महिलाओं ने अथक प्रयास किये हैं। प्रत्येक गांव में पच्चीस-पच्चीस महिलाओं की पानी पंचायत बनायी गई है, महिला सदस्य जल संरचनाओं के निर्माण व रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें सम्मान से जल सहेलियां कहकर बुलाया जाता है। सही मायनो में ये जल सहेलियां बुंदेलखंड के लिये भगीरथ बन गई हैं। छतरपुर के अंगरोठा गांव में आसपास की पंचायतों की चार सौ से अधिक महिलाओं ने पहाड़ को काटने के संकल्प को हकीकत में बदला। पहाड़ के करीब साढ़े तीन सौ फीट हिस्से को काटकर एक ऐसी नहर बनायी गई, जिससे पहाड़ों का बरसाती पानी गांव के बड़े तालाब में भरने लगा। इसके साथ ही बरसाती बछेड़ी नदी को भी नया जीवन मिला। दरअसल, बुंदेलखंड में जल संरचनाओं को गढ़ने के जो भगीरथ प्रयास हुए हैं, अंगरोठा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। निस्संदेह जल संकट की त्रासदी महिलाएं ही झेलती हैं, इसीलिए उन्होंने नई जल संरचना के निर्माण का बीड़ा उठाया।

दरअसल, गंभीर संकट से जूझते बुंदेलखंड को यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो साढ़े तीन हजार करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसका लक्ष्य सूखे को खत्म करके क्षेत्र से पलायन रोकना भी था। इस योजना के तहत अंगरोठा में चालीस एकड़ का तालाब बनाया गया था जो जंगल से तो जुड़ा था मगर यहां पानी आने का रास्ता बीच में एक पहाड़ आने से अवरुद्ध था। बड़े इलाके का पानी बछेड़ी नदी से होकर निकल जाता था। स्थायी जल स्रोत न होने से यह तालाब बरसात के बाद सूख जाता था। शेष महीनों में गांव में जल संकट बना रहता था। गांव की महिलाओं ने क्षेत्र में सक्रिय समाजसेवी संस्था व जल जोड़ो अभियान के सहयोग से इस भगीरथ प्रयास को अमलीजामा पहनाने का संकल्प लिया। पहाड़ को काटकर नहर को तालाब से जोड़ दिया गया।

इस अभियान को नेतृत्व देने वाली बबीता राजपूत कहना है कि केवल अंगरोठा की ही नहीं, निकटवर्ती कई गांवों की महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर श्रमदान के लिये आती थीं। पहले मनरेगा के तहत कार्य करवाने का विचार आया लेकिन महिलाओं ने खुद ही संकल्प को पूरा किया। करीब डेढ़ साल की अथक मेहनत से जीवनधारा गांव तक पहुंची। पहाड़ में विद्यमान ग्रेनाइट के पत्थरों को हटाना एक बड़ी बाधा थी, जिन्हें काटने के लिये मशीनों की भी मदद ली गई। इतना ही नहीं, इस काम में जितने पेड़ काटे गये, उसी संख्या में महिलाओं ने नये पौधे भी लगाये ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। बबीता बताती है कि इस प्रयास से जहां गांव का तालाब लबालब भर गया, वहीं गांव में भूजल का स्तर भी समृद्ध हुआ है। साथ ही मरणासन्न बरसाती बछेड़ी नदी को नया जीवन मिल गया, जो सदानीर बनी रहेगी।

दरअसल, बबीता के नेतृत्व में महिलाओं ने वर्षा जल सहेजकर गांव की दशा सुधारकर समृद्धि की दिशा बदल दी है। जल जोड़ो अभियान के अनुसार तालाब में सत्तर एकड़ तक पानी भर रहा है। भूजल स्तर में वृद्धि से सूखे कुएं भी जीवंत हुए हैं और हैंडपंप भी कम गहराई में पानी दे रहे हैं। पशु धन के लिये भी अब पानी का संकट नहीं रहा। अब खेती में समृद्धि की संभावनाएं हकीकत बन गई हैं।

बबीता इस बात को स्वीकारती है कि यह लक्ष्य हासिल करना सरल कार्य नहीं था। लेकिन क्षेत्र की महिलाएं तन-मन से साथ जुटीं और लक्ष्य हकीकत में बदल गया। इसमें उन प्रवासी श्रमिकों की भी भूमिका रही जो कई दिन पैदल चलने के बाद गांव पहुंचते थे। इस काम में जल जोड़ो अभियान के संयोजक मानवेंद्र का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा। इस अभियान को लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिया गया। जिससे इस पठारी क्षेत्र के सूखे खेत अब सोना उगलने को तैयार हो गये हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पानी के कारण गांव-घर छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। बारिश?होने के बाद अंगरोठा का तालाब लबालब पानी से भर गया। इस उपलब्धि से खुश बबीता कहती है कि इस सफलता से उनकी निजी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। लोग उनके काम को सराह रहे हैं। वह कहती है कि पहले लोग उन्हें बबीता कहते थे, अब बबीता जी कहने लगे हैं। यह सुनना अच्छा लगता है।

महिला कैदी

बढ़े सुविधाओं का दायरा

डॉ. दर्शनी प्रिय

देशभर की जेलों में महिला कैदियों की संख्या दयनीय है। सजायाफ्ता गर्भवती महिला कैदियों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1,339 जेलों में 1,732 महिला कैदी अपने 1,999 बच्चों के साथ रह रही हैं। इनमें 1,376 अंडरट्रायल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में कुल महिला जेलों की संख्या केवल 24 है। इनमें 2019 तक महिला कैदियों की संख्या बढ़कर 651 हो गई। कई राज्य हैं जहां केवल एक महिला जेल है। इनमें यूपी, प. बंगाल और महाराष्ट्र प्रमुख हैं। जाहिर है इन राज्यों में महिला कैदियों को सामान्य कारागार में ही रखा जाता है।

हाल के वर्षो में जेल में महिला कैदियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन कारावास के भीतर उन्हें समायोजित करने संबंधी विधि-व्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। महिला कैदियों को लेकर न तो कोई एकीकृत व्यवस्था है और न ही महिला विशेष जेलों की अवधारणा। इसी अनदेखी के चलते महिला जेलों की संख्या अब तक चौबीस को पार नहीं कर सकी है। वहां भी उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रजनन संबंधी तमाम मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है। वैसे भी देश की अधिकतर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पेयजल, साफ-सफाई, चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी, शौचालयों का अभाव ऐसे बिंदु हैं, जहां त्वरित कार्यवाही की जरूरत है। ऐसे में महिला कैदियों की मानसिक और शारीरिक त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अन्य मौलिक सुविधाओं से इतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो हालात और भी भयावह हैं। दिसम्बर, 2018 तक 3,220 की जगह केवल 1,914 मेडिकल स्टाफ ही इन जेलों में तैनात थे जो कुल क्षमता का करीब दो-तिहाई हिस्से से भी कम है। हैरत की बात है कि पूरे देश की जेलों में केवल 667 एंबुलेंस ही उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में तो एक भी एंबुलेंस नहीं है। सामान्य उपचार केंद्रों की भी किल्लत है।

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ज्यादातर कैदियों को बड़े अस्पताल जाना पड़ता है। महिला कैदियों को महावारी, गर्भावस्था, पीसीओडी, जननांग संक्रमण आदि से जुड़ी प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जेल प्रशासन के आसरे रहना होता है। जेल मैनुअल के नियमानुसार महिला कैदी को जेल में रखने से पूर्व उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाना जरूरी है। गर्भवती होने पर उसकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल तथा बच्चे के जन्म तक उचित देखभाल की सिफारिश की गई है। लेकिन ज्यादातर मामलों में अनदेखी की जाती है। हालांकि जेल नियम के अनुसार छह साल तक के बच्चों को ही मां के साथ जेल में रहने की इजाजत है। इस लिहाज से 1-6 वर्ष के बच्चों को समुचित देखभाल की दरकार होगी। विडंबना है कि देश की सत्तर प्रतिशत जेलों में इन बच्चों के लिए न तो पालनाघर हैं, और न ही प्ले स्कूल। कैदी मांओं की अनदेखी से अजन्मे शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जाहिर है कि पोषण से वंचित जच्चा से जन्मा बच्चा कुपोषित और रुग्ण होगा जिससे बाद में स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिभार ही बढ़ेगा।

बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं। कल्याणकारी राज्य का कर्त्तव्य है कि नागरिकों को शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराए। स्वस्थ माहौल में ही किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। मानसिक और रचनात्मक विकास के लिए बच्चे का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट बताती है कि 2018-19 में पूरे देश में कैदियों पर 1,776 करोड़ रु पये खर्च किए गए जो कुल खर्च का केवल 33.61 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि कैदियों की जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लचर वित्त प्रबंधन की शिकार हैं। महिला कैदी किसी कुव्यवस्था की शिकार न हों। सम्मान से जेलों में समय बिताएं। इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की तत्काल जरूरत है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देने आवश्यकता है। बेहतर होगा कि राज्य बाल संरक्षण आयोग ऐसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, भरण-पोषण का जिम्मा उठाए। साथ ही, उन्हें हॉस्टल भेजने तथा उनके स्कूल में दाखिले की भी जिम्मेदारी उठाए। मानसिक पीड़ा से गुजर रही कैदियों के लिए बेहतर काउंसलिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए भी समेकित प्रयास किए जाएं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पेटीएम ने किया ऐलान, मिनी एप डेवलपर्स को देगा 10 करोड़ रुपये का फंड

नई दिल्ली। गूगल के साथ जारी अपनी लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए देश के डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम ने गुरूवार को कहा कि वह देश के मिनी एप डेवलपर्स के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित कर रहा है। दरअसल, मिनी एप्प डेवलपर्स कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए पेटीएम के संस्थापक विजय शंकर शर्मा ने यह बात कही। पेटीएम संस्थापक ने कहा कि वह 10 लाख मिनी एप्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वह वह गूगल द्वारा अनुचित चार्ज के खिलाफ हैं। बता दें कि गूगल ने बीते दिनों कहा था कि अब जितने भी डेवलपर्स उसके प्लेस्टोर के साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें प्लेस्टोर बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत होना होगा। हालांकि गूगल ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय डेवलपर्स के लिए एल्टनेटिव पेमेंट सिस्टम अपनाने की समय सीमा बढ़ा दी है और अब वे 31 मार्च, 2022 तक प्ले स्टोर बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हो सकते हैं। गूगल द्वारा अपने प्ले स्टोर से हटाए जाने से नाराज पेटीएम ने सोमवार को स्थानीय एप्प डेवलपर्स को मदद पहुंचाने और उनकी नवीन सोच को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से एक एंड्रायल मिनी एप्प स्टोर लॉन्च किया था। पेटीएम ने कहा था कि वह अपने नई मिनी एप की लिस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने एप के माध्यम से करेगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।पेमेंट के लिए डेवलपर्स अपने यूजर्स को पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यूपीआई, नेट बैंकिंग और काड्र्स का ऑब्शन दे सकते हैं।

प्याज के इन किस्मों के निर्यात को मिली अनुमति, कीमतें बढ़ने की आशंका

नई दिल्ली: सरकार ने प्याज की बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्मों के सीमित निर्यात की अनुमति दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इन दोनों किस्मों के प्याज की 31 मार्च, 2021 तक 10-10 हजार मीट्रिक टन निर्यात किया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अमित यादव ने एक बयान में यह जानकारी दी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के इस फैसले किसानों का सशक्तिकरण होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने भले ही बहुत कम मात्रा में निर्यात की अनुमति दी हो लेकिन इससे कीमतें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। बेंगलोर रोज ओनियन के निर्यात की अनुमति केवल चेन्नई पोर्ट से होगी और निर्यात 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए निर्यातक को कर्नाटक सरकार के हॉर्टीकल्चर कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना होगा। कृष्णापुरम ओनियन की अनुमति भी केवल चेन्नई पोर्ट से होगी। इसके लिए निर्यातक को आंध्र प्रदेश सरकार से सर्टिफिकेट लेना होगा।

किन देशों को होता है निर्यात

कर्नाटक के किसानों ने को केंद्र से आग्रह किया था कि उपज को नुकसान से बचाने के लिये 'बेंगलुरु रोज' किस्म के 10 हजार टन प्याज के निर्यात को अनुमति दी जाए। बेंगलुरू ग्रामीण, कोलार और चिक्काबल्लापुर जिलों में किसानों ने इस साल प्याज की इस किस्म के 10,000 टन से अधिक का उत्पादन किया है। यह किस्म दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड और ताइवान को निर्यात की जाती है क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी ज्यादा मांग नहीं है।

खुदरा मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में चार प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद: आरबीआई

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति के चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक तय लक्ष्य के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि, सितंबर तिमाही के अंत तक इसके खुदरा मुद्रास्फीति के लिए तय 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर 6.8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। दास ने केंद्रीय बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। समिति ने जब तक आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष के और अगले वर्ष के दौरान- मौद्रिक नीति के उदार रुख को भी बनाए रखने का निर्णय लिया, ताकि आने वाले समय में मुद्रास्फीति को तय दायरे में रखना सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के प्रतिकूल असर को दूर करते हुए आर्थिक वृद्धि में टिकाऊ आधार पर सुधार लाया जा सके। सरकार की तरफ से मौद्रिक नीति समिति को खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें दो प्रतिशत घट-बढ़ की गुंजाइश है।

रिजर्व बैंक ने नीतिगत बयान में कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 2020-21 की दूसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके बाद मुद्रास्फीति के तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत तक और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।

बयान में कहा गया, ''कोविड-19 का टीका उपलब्ध हो जाने के साथ 2021-22 में आपूर्ति श्रृंखला में सामान्य स्थिति लौट जाने, मानसून सामान्य रहने और किसी बाह्यजनित या नीतिगत झटके नहीं आने की उम्मीद के आधार पर संरचनात्मक मॉडल के अनुमान से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।''

एक लाख करोड़ रुपये का हमेशा उपलब्ध टीएलटीआरओ लायेगा रिजर्व बैंक

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिये एक लाख करोड़ रुपये का हमेशा उपलब्ध लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टारगेटेड एलटीआरओ) करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा, ''यह निर्णय लिया गया है कि नीतिगत रेपो दर से जुड़ी परिवर्तनशील दरों पर तीन साल तक की परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के साथ एक लाख करोड़ रुपये तक का टीएलटीआरओ (खुले बाजार में खरीद बिक्री) किया जायेगा।'' रिजर्व बैंक ने कहा कि इसके तहत उपलब्ध की गयी नकदी को बैंक कॉरपोरेट बांड, वाणिज्यिक दस्तावेज , गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) और विशिष्ट क्षेत्रों के निकायों के द्वारा जारी कॉरपोरेट बांड, वाणिज्यिक दस्तावेज और गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में लगाया जायेगा में लगाना होगा। यह निवेश उनके पर ऐसी प्रतिभूतियों में 30 सितंबर 2020 तक बकाया निवेश के अतिरिक्त होगा।'' यह योजना 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में ने नीतिगत दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है और रुख को उदार बनाये रखने का निर्णय लिया।

बढ़ती मांग से रिफाइंड सोयातेल वायदा कीमतों में सुधार

नयी दिल्ली.

सटोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार को बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में शुक्रवार को रिफाइंड सोयातेल की कीमत 3.9 रुपये के सुधार के साथ 919.2 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गई। एनसीडीईएक्स में रिफाइंड सोयातेल के अक्टूबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 3.9 रुपये अथवा 0.43 प्रतिशत के सुधार के साथ 919.2 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गई जिसमें 15,010 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार, रिफाइंड सोयातेल के नवंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6.6 रुपये अथवा 0.72 प्रतिशत के सुधार के साथ 926.3 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गई जिसमें 36,190 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में रिफाइंड सोयातेल कीमतों में सुधार दर्ज हुई।

आम आदमी के लिए बड़ी खबर: अब बन रहा ग्रीन राशन कार्ड, जानिए इसके बारे में

बिजनेस डेस्क:

मोदी सरकार के निर्देश पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई राज्य सरकारें ग्रीन राशन कार्ड योजना ले कर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को एक रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अबतक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएगी।हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर में या 2021 के शुरुआत में कई राज्य सरकारें यह योजना लागू करने जा रही है। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी 15 नवंबर से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्डधारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

इस तरह आवेदन कर सकते हैं

ग्रीन राशन कार्ड पाने के लिए भी आपको राशन कार्ड की तरह ही तरीका अपनाना होगा। जनसेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र पर ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ग्रीन राशन कार्ड पाने के लिए आवेदकों को कई तरह की जानकारियां साझा करनी होगी। जैसे- आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता का डिटेल, आवासीय और वोटर आईकार्ड भी ग्रीन राशन कार्ड के लिए अनिवार्य होगा। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।

एक रुपए प्रति किलो अनाज मिलेंगे

ग्रीन राशन कार्ड के तहत राज्य सरकारें गरीब लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देगी। देश के कई राज्यों के सीएम के द्वारा यह योजना शुरू की गई हैं। इस योजना की सारी जवाबदेही राज्य सरकारों के पास रेहगी। यह योजना लागू करने वाले राज्य मुखिया, पंचायत सेवक और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों के लिए बनने वाले ग्रीन कार्ड के संबंध में चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। बीपीएल कार्डधारकों की ही ग्रीन राशन कार्ड मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन लागू और शुरू करने का काम राज्यों के द्वारा हो रहा है। इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्डधरयकों को ही मिलेगा, लेकिन बीपीएल कार्डधारकों को देखा जाएगा कि वह कितना गरीब हैं।

दूसरी तिमाही में आवास बिक्री में 43 प्रतिशत, दफ्तर पट्टे पर लेने में 70 प्रतिशत गिरावट

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी के बीच देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में पट्टे पर कार्यालय स्थल लेने की मांग 70 प्रतिशत घटी है। वहीं इस दौरान, आवास बिक्री में भी 43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इससे पिछले तिमाही से यदि तुलना की जाये तो स्थिति में सुधार आया है। संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी एक रपट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में स्थिति में सुधार आया है। दफ्तरों को पट्टे पर लेने में 81 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी है। गौरतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाये गए लॉकडाउन में बीत गया था। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा जुलाई-सितंबर तिमाही के आंकड़े प्रोत्साहित करने वाले हैं। लेकिन हम अभी तक उबरे नहीं है। समीक्षा तिमाही में बिक्री में सुधार होना काफी रोमांचित करने वाला है। बैजल ने अगले साल संपत्ति बाजार में मांग के 2019 के स्तर पर अथवा उससे भी आगे निकलने की उम्मीद जतायी। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में आठ शहरों में आवास बिक्री 43 प्रतिशत गिरकर 33,403 इकाई रही। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 58,183 मकान बिके थे।

इस साल जीडीपी में 9.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान- RBI

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के असर के कारण चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिनों तक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चली बैठक के निष्कर्षों की घोषणा करते हुए कहा कि जीडीपी चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि की राह पर लौट सकती है और 0.5 प्रतिशत बढ़ सकती है।

जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की गिरावट

दास ने कहा विभिन्न कारकों और कोविड-19 की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के नकारात्मक रहने का अनुमान है। जीडीपी में इस दौरान 9.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, जो 9.8 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है। जीडीपी गिरावट तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि इसमें चौथी तिमाही में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 20.6 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।

लॉकडाउन से जीडीपी प्रभावित

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आयी है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये देश भर में लगाये गये लॉकडाउन से सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में आया व्यवधान है। दास ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग में सुरक्षित आपसी दूरी के प्रावधान तथा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सुधार होने की फिलहाल कम संभावना है।

निजी निवेश और निर्यात दोनों के कम रहने की आशंका

आरबीआई गवर्नर ने कहा संपर्क पर निर्भर सेवा क्षेत्र को कोविड से पहले के स्तरों को फिर से हासिल करने में समय लगेगा, लेकिन विनिर्माण कंपनियों के क्षमता के इस्तेमाल में तीसरी तिमाही में सुधार आने की और चौथी तिमाही में इसके गति पकड़ने की उम्मीद है। निजी निवेश और निर्यात दोनों के कम रहने की आशंका है, विशेषकर इस कारण कि बाहरी मांग अभी भी सुस्त है।मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को शुरू हुई बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है।

उबरने की गति तीन प्रकार के होने के अनुमान

दास ने कहा अप्रैल- जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गयी है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र और ऊर्जा खपत में तेजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत महामारी के प्रसार की दूसरी लहर को रोकते हुए वायरस की घातक चपेट से बाहर निकलने और कोविड से पहले की वृद्धि दर हासिल करने के लिये तैयार है। आर्थिक स्थिति के उबरने के प्रकार के बारे में जारी बहस के संदर्भ में दास ने कहा कि मुख्य रूप से उबरने की गति तीन प्रकार के होने के अनुमान हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र अलग गति दिखा रहे हैं और यह क्षेत्र विशेष की वास्तविकताओं पर निर्भर करेगा।

जल्द सामान्य होने की उम्मीद

उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियां, एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां), दोपहिया व यात्री वाहन, ट्रैक्टर, दवा और बिजली विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन आदि जैसे क्षेत्रों ने महामारी के समक्ष दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। ऐसे क्षेत्रों के जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। इसके अलावा कृषि विपणन और शीत भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण समेत मूल्य श्रृंखला में सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव और टीकों के उत्पादन व वितरण के लिये क्षमता निर्माण आदि ने पहले से ही निवेश के नये आयाम खोले हैं।

जीएसएफसी ने कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटिड कैल्शियम नाइट्रेट की देशी किस्म की पेशकश की

नयी दिल्ली,

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (जीएसएफसी) ने शुक्रवार को कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटिड कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्मों को पेश किया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में इन उत्पादों को पेश किया। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग खेती के लिए, पानी में घुलनशील उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, इस उत्पाद का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में और सीमेंट कंक्रीट की ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। भारत में पहली बार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन युक्त कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण किया जा रहा है। अब तक इसे दूसरे देशों से आयात किया जाता था। एक सरकारी बयान में कहा गया कि ये दोनों उत्पाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के सोलन और गुजरात के भावनगर में खुदरा बाजार में पेश किए गए। मंडाविया ने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उत्पाद घरेलू बाजार में काफी सफल होंगे।''

उन्होंने कहा कि जीएसएफसी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट आह्वान के जबाव में ''आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि'' की ओर यह निर्णायक कदम उठाया है।

मंडाविया ने कहा कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्म, आयातित उर्वरक की तुलना में देश में किसान समुदाय को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो दो उत्पाद पेश किये गये हैं उन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किया गया है। उर्वरक मंत्रालय ने बयान में कहा कि जीएसएफसी के पास मौजूदा समय में इन दोनों उत्पादों के निर्माण के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता है। तीन महीने के भीतर, उत्पादन प्रति वर्ष 15,000 टन तक बढ़ने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है जीएसएफसी ने अगले नौ से 12 महीने में उत्पादन को बढ़ाकर 30,000 टन करने की योजना बनाई है। पिछले साल भारत ने 225 करोड़ रुपये में लगभग 1.25 लाख टन कैल्शियम नाइट्रेट का आयात किया था। इसमें से 76 फीसदी चीन और बाकी देशों जैसे नॉर्वे और इजरायल से आयात किया गया था।

जीएसएफसी ने खुद पिछले साल 4,600 टन का आयात और बिक्री की थी। देश भर स्थित जीएसएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इस डिजिटल लॉन्च में भाग लिया।

रेलवे का नया कदम, सफर के दौरान कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, अगले स्टेशन पर मिलेगा सामान

नई दिल्ली:

रेल यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए रेलवे ने एक और मजबूत कदम उठाया है। अब यात्रा के दौरान रेल यात्री खरीदारी भी कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान शॉपिग करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया है। यात्रा के दौरान सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य जरूरी सामान की मोबाइल के माध्यम से डिजिटल खरीदारी की जा सकेगी। ट्रेन में सफर के दौरान यात्री द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा तो आने वाले निकट स्टेशन पर उन्हें सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें एमआरपी पर उनके इच्छित सामान को उपलब्ध कराया जाएगा।

ट्रॉयल शुरू किया गया

रेलवे ने फिलहाल शॉपिग की यह सुविधा पश्चिमी रेलवे में ट्रायल के तौर पर शुरू की है। यह प्रयोग सफल हो जाने के बाद नये वित्तीय वर्ष में दक्षिण-पूर्व रेलवे के ट्रेनों में भी इस सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बताया जाता है कि यह पहल रेलवे द्वारा डिजिटल खरीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस सिलसिले में रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यह पहल पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद-मुंबई कर्णावती एक्सप्रेस और डबल डेकर ट्रेन में की गई है। इसके बाद भारतीय रेल के अन्य जोन में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

वहीं, दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी संजय घोष कहते हैं कि उन्हें इस बारे में अभी अधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है। यह मामला बोर्ड स्तर का है, जिस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा।

कालेधन पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी, स्विटजरलैंड ने सौंपी दूसरी लिस्ट

नई दिल्ली:

भारत को सूचनाओं की स्वतः आदान-प्रदान व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों और संस्थाओं के स्विस बैंक खातों की जानकारी का दूसरा सेट मिला है, जो कथित रूप से विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। भारत उन 86 देशों में शामिल है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने इस साल एईओआई पर वैश्विक मानक ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी साझा की है। भारत को एईओआई (सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान) के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट मिला था। उस समय इसमें 75 देश शामिल थे। एफटीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा इस साल सूचना के आदान-प्रदान में लगभग 31 लाख वित्तीय खाते शामिल हैं। वर्ष 2019 में भी करीब इतने ही खातों की जानकारी दी गई थी। हालांकि, बयान में 86 देशों के बीच भारत के नाम का अलग से उल्लेख नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्राहकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है। अधिकारियों ने आगे कहा कि इस साल 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने 30 लाख से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की है और इसमें एक ''बड़ी संख्या'' भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है। उन्होंने कहा कि स्विस अधिकारियों ने भारत के अनुरोध पर पिछले एक साल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है, जिनके खिलाफ कर चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच चल रही थी। ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं, जो 2018 से पहले बंद हो चुके हैं। एईओआई केवल उन खातों पर लागू होता है, जो 2018 के दौरान सक्रिय थे या इस बीच बंद किए गए। इनमें से कुछ मामले भारतीयों द्वारा पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमैन आइलैंड जैसे स्थानों की संस्थाओं में जमा धन से संबंधित हैं। इनमें से ज्यादातर व्यापारी हैं, जबकि कुछ राजनेता और उनके परिजन भी शामिल हैं। अधिकारियों ने हालांकि गोपनीयता का हवाला देते हुए भारतीयों के मौजूदा खातों की संख्या या इनमें जमा धनराशि के बारे में ब्यौरा देने से इनकार किया। स्विस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है।

इन जानकारी से कर अधिकारियों को यह पता करने में मदद मिलेगी कि क्या करदाताओं ने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों के बारे में सही जानकारी दी है। इस तरह का अगला आदान-प्रदान सितंबर 2021 में होगा। स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ और इसमें 36 देश शामिल थे। उस समय भारत इस सूची में शामिल नहीं था।

61 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला, डीजीजीआई ने इन कंपनियों के मालिकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली।

जीएसटी की खुफिया शाखा डीजीजीआई ने कुछ निर्यातक कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और नकद रिफंड के रूप में 61 करोड़ रुपये हथियाने का पर्दाफाश किया है। बयान के मुताबिक जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) को यह खबर मिली थी कि कुछ निर्यातक कंपनियां फर्जी फर्मों के चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से फायदा उठा रही हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की। बयान में कहा गया आईटीसी का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल निर्यात की गई वस्तुओं पर आईजीएसटी चुकाने के लिए हुआ और बाद में उसके नकद रिफंड का दावा किया गया। इस तरह सरकारी खजाने को दोहरा नुकसान पहुंचा। बता दें कि इस तरह हासिल की गई आईजीएसटी रिफंड की राशि लगभग 61 करोड़ रुपये है। डीजीजीआई ने इन निर्यात कंपनियों के नियंत्रकों और आपूर्ति करने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोलकाता में मेट्रो स्टेशन का नाम होगा इंडियन फुटबाल एसोसिएशन

कोलकाता। युवा भारती क्रिडागंना के पास बने मेट्रो स्टेशन का नाम इंडियन फुटबाल एसोसिएशन साल्ट लेक स्टेडियम रखा गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश में किसी खेल संघ का नाम इस तरह से किसी मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हो। आईएफए के सचिव जयदीप मुखर्जी ने कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (केएमआरसी) को धन्यवाद देते हुए कहा, बंगाल में फुटबाल ऐसी चीज है जो राज्य में हर किसी को बांधे रखती है। हम इसे खेल के भी हितधारकों के बड़े सम्मान के रूप में देखते हैं। यह हमारा शहर है, यह हमारा खेल है। उन्होंने कहा, मैं केएमआरसी और पश्चिम बंगाल का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। यह महान लोगों और उन लोगों को श्रद्धंजलि है जो भारतीय फुटबाल को आगे ले गए हैं। स्टेशन का नाम फुटबाल पर रखना खेल से जुड़े लोगों के बेहद उत्साह की बात है। यह देश की फुटबाल के लिए गर्व का पल है। 1893 में बना आईएफए देश का सबसे पुराना फुटबाल संघ है अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट सुब्रत दत्ता ने कहा, दशकों से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए करते हैं। स्टेशन का नाम आईएफए साल्ट लेक स्टेडियम रखना प्रशंसकों को एक अलग अपनेपन का एहसास कराएगा। मैं इसे एक अलग मुहिम के तौर पर देखता हूं जो प्रशंसकों को तेजी से फुटबाल से जोड़ेगा।

फ्रेंच ओपन

फाइनल में केनिन, दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब पर नजरें

पेरिस।

आस्ट्रेलियन ओपन विजेता सोफिया केनिन ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा को मात दी। अमेरिका की 21 साल की केनिन ने सातवीं सीड क्वितोवा को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से हरा फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में केनिन का सामना पोलैंड की युवा खिलाड़ी इगा स्वितेक से होगा जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में नादिया पोडोरोस्का को 6-2, 6-1 से हरा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। बीबीसी ने केनिन के हवाले से लिखा, क्वितोवा काफी मुश्किल खिलाड़ी हैं। उनका खेल काफी आक्रामक है और उनकी सर्विस शानदार है। मुझे अपने आप पर गर्व है। यह शानदार मैच था और मैं काफी खुश हूं। केनिन और स्वितेक एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं लेकिन टूर पर नहीं बल्कि चार साल पहले जूनियर स्तर पर। डबल्यूटीए की वेबसाइट ने केनिन के हवाले से लिखा, मैंने आस्ट्रेलिया में खिताब जीता है। बीते दो मैचों में मैंने काफी मुश्किल मैच खेले हैं। मैं फाइनल में पहुंचकर काफी उत्साहित हूं। यह अविश्वनसनीय है। मैं आज इस पल का लुत्फ लेना चाहती हूं और कल होने वाले फाइनल के लिए तैयार रहना चाहती हूं। चौथी सीड इस खिलाड़ी का इस साल रिकार्ड 16-1 का है। उन्होंने आस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा को हरा अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। अपनी विपक्षी के बारे में केनिन ने कहा, हम फ्रेंच ओपन में जूनियर में एक साथ खेले हैं। वो काफी करीबी मैच था। मैं फाइनल के लिए अच्छे से तैयारी करूंगी और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। स्वितेक ओपन इरा में रोलां गैरों के फाइनल में पहुंचने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी हैं। वहीं किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जाने वाली अपने देश की दूसरी। उनसे पहले 2012 में एजिन्स्का रादवांस्का ने विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई थी। स्वितेक फाइनल के अपने परिणाम को लेकर चिंतित नहीं है और उनका ध्यान अपना सर्वश्रेष्ठ खेलने पर है। फाइनल की राह में उन्होंने रोमानिया की सिमोना हालेप को मात दे सबसे बड़ा उलटफेर किया था जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा।

उन्होंने कहा, सोफिया, इस साल शानदार फॉर्म में हैं। मैं उस तरह की खिलाड़ी हूं जो दबाव में बेहतर खेलती हूं। मैं इसलिए ज्यादा प्रभावशाली रही हूं क्योंकि मैं ज्यादा एकाग्र रहती हूं। मैं अपने विपक्षी खिलाड़ी को उनकी सर्वश्रेष्ठ टेनिस नहीं खेलने देती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं शनिवार को यह करूंगी। मुझे किसी तरह की उम्मीद नहीं है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जीतूंगी या हारूंगी। मैं सिर्फ अपनी सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेलूंगी। मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं है।

चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ बल्लेबाज सरकारी नौकरी की तरह समझते हैं : सहवाग

दुबई।

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि कुछ बल्लेबाज टीम में खेलना सरकारी नौकरी के समान समझते हैं। आईपीएल-13 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई अच्छी फॉर्म में नहीं है। छह मैचों में से उसे सिर्फ दो में जीत मिली है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई को 10 रनों से हरा दिया था। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शेन वाटसन और अंबाती रायडू जब तक क्रीज पर थे चेन्नई जीतती दिख रही थी लेकिन जैसे ही यह दोनों आउट हुए टीम बिखर गई। सहवाग ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, इस लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए था। लेकिन केदार जाधव और रवींद्र जडेजा ने जो खाली गेंदें खेलीं उसने काम खराब कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे विचार में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज टीम को सरकारी नौकरी की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि वो प्रदर्शन करें या नहीं उनकी सैलरी आती रहेगी चेन्नई की टीम अंकतालिका में इस समय छठे स्थान पर है। शनिवार को अपने अगले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा।

डब्ल्यूबीबीएल-6 : होबार्ट हरिकेंस से जुड़ीं न्यूजीलैंड की हेले जेनसेन

सिडनी। न्यूजीलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी हेले जेनसेन ने महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के छठे सीजन में होबार्ट हरिकेंस के साथ करार किया है। लीग की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है। हरिकेंस के महा प्रबंधक स्कॉट बार्नेस ने कहा कि जेनेसन का हाल ही में आस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन और टी-20 विश्व कप-2020 में प्रदर्शन अच्छा रहा था इसलिए टीम ने उन्हें टीम में शामिल किया गया है। बार्नेस ने कहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट सिस्टम जेनसेन के लिए शानदार रहा है और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि वह टीम में अच्छे से रम जाएंगी। उन्होंने कहा, वह न्यूजीलैंड टीम के लिए सबसे पहले 2013-14 सीजन में खेली थीं। इस साल हुए विश्व कप मैच के पहले मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था जो बताता है कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। हरिकेंस की टायला व्लामिंक और मैसी गिब्सन चोट के चलते इस साल टीम के साथ सफर नहीं करेंगी।

आईपीएल-13

धोनी के सामने होगी कोहली की चुनौती

दुबई।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें संस्करण में शनिवार को दूसरे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का सामना विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। चेन्नई ने जहां छह मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं वहीं बेंगलोर ने पांच मैचों में तीन जीत हासिल की है। चेन्नई को पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार मिली थी और यह हार, जीत के करीब पहुंच कर मिली थी। एक समय जीतती दिख रही चेन्नई ने आखिरी के ओवरों में लगातार विकेट खोकर मैच गंवा दिया था। शेन वाटसन और अंबाती रायडू टीम को मैच जिताते दिख रहे थे लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद और फिर कप्तान धोनी के जाने के बाद टीम संभल नहीं पाई थी। वाटसन और फाफ डु प्लेसिस शानदार फॉर्म में हैं और रायडू भी अपना योगदान दे रहे हैं। रवींद्र जडेजा भी इस सीजन एक अर्धशतक जमा चुके हैं। लेकिन फाफ और वाटसन को छोड़कर कोई निरंतर अच्छा नहीं कर पा रहा है और टीम को जीत के लिए एक संयुक्त प्रदर्शन की जरूरत है। गेंदबाजी में दीपक चहर और सैम कुरैन सहित शार्दूल ठाकुर ने अच्छा किया है। यह सभी किफायती साबित हुए हैं। पिछले मैच में धोनी ने पीयूष चावला के स्थान पर कर्ण शर्मा को मौका दिया था। कर्ण मे चार ओवरों में 25 रन देकर दो विकेट लिए थे। इसलिए इस मैच में भी उनके खेलने की पूरी संभावना है। कोलकाता के खिलाफ धोनी ने जडेजा को गेंदबाजी का मौका नहीं दिया था।

इस मैच में जडेजा को मौका मिलता है या नहीं यह देखना होगा। पिछले कुछ मैचों में चेन्नई की गेंदबाजी ने पहले से बेहतर किया है और इसलिए धोनी को यहां राहत है लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजी है जहां वो सभी से योगदान की उम्मीद करेंगे, खुद से भी। जहां तक बेंगलोर की बात है तो एरॉन पिंच, देवदत्त पडिकल, कप्तान विराट कोहली और अब्राहम डिविलियर्स के रहते उसकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, निचले क्रम में मोइन अली के आने से टीम को मजबूत मिली है। गेंदबाजी में नवदीप सैनी और इसुरु उदाना ने टीम का भार संभाला है और स्पिन में युजवेंद्र चहल, कोहली के तुरुप के इक्के हैं।

वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में प्रभावित किया था। इस मैच में भी कोहली को सभी से पिछले प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

संक्षिप्त समाचार

बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम को डेनमार्क की फ्लाइट में बैठने से रोका

नई दिल्ली । भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने कहा है कि उन्हें शुक्रवार सुबह बेंगलुरू से डेनमार्क की फ्लाइट में बैठने से रोक दिया गया। जयराम को डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज के लिए रावना होना था। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और शुभांकर डे दिल्ली से एयर फ्रांस के विमान से बीती रात रवाना हो गए जबकि जयराम को शुक्रवार सुबह ब्रिटिश एयरवेज से रवाना होना था। 33 साल के जयराम ने लगातार ट्वीट करते हुए बताया उनके पास सी स्चेनगेन वीजा और कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें नहीं जाने दिया गया। जयराम ने एयर फ्रांस से अपील करते हुए कहा कि वह उन्हें डेनमार्क जाने में मदद करें। उन्होंने लिखा, मुझे आज रात को बेंगलुरू से डेनमार्क, डेनमार्क ओपन खेलने के लिए जाना था। मेरे पास सी टाइप वीजा था और कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट भी और आयोजकों का आमंत्रण पत्र भी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या में एयर फ्रांस से जा सकता हूं। उन्होंने लिखा, मुझे इस सुबह ब्रिटिश एयरवेज से जाना था। बाकी की भारतीय टीम बीती रात दिल्ली से एयर फ्रांस से रवाना हो चुकी है उनके पास भी सी टाइप स्चेनगेन वीजा था जो मेरे पास भी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग भी किया। यह सुपर 750 टूर्नामेंट ओडेंसे में 13 से 18 अक्टूबर के बीच खेला जाना है।

आईपीएल-13: औरेंज कैप राहुल और पर्पल कैप रबादा के पास

दुबई। आईपीएल-13 के 22वें मैच के समापन के बाद औरेंज कैप किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल के पास ही है और पर्पल कैप भी दिल्ली कैपिटल्स के कागिसो रबादा के पास है। आईपीएल में गुरुवार को सनाइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को दुबई इंटरनेशन स्टेडियम में खेले गए मैच में 69 रनों से हरा दिया। राहुल हालांकि इस मैच में सिर्फ 11 रन ही बना पाए लेकिन वह दूसरे स्थान पर काबिस फाफ डु प्लेसिस से अंतर बढ़ाने में कारगर रहे। राहुल के अब छह मैचों में 313 रन हो गए हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर चेन्नई के फाफ हैं जिनके नाम छह मैचों में 299 रन हैं। पंजाब के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 281 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजों में रबादा पांच मैचों में 12 विकेट लेकर पहले स्थान पर बने हुए हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बाउल्ट हैं। बुमराह के नाम 11 विकेट हैं और बाउल्ट के नाम 10 विकेट हैं। अंकतालिका में मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर काबिज है। उसेक छह मैचों में आठ अंक हैं। दिल्ली दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है।

वॉर्नर IPL में 50 बार 50 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने

डिजिटल डेस्क।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के 22वें मैच में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रन से हराया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके बाद पंजाब को 16.5 ओवर में ही 132 रन पर ऑलआउट कर हैदराबाद ने मैच जीता। हैदराबाद की इस जीत में सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और कप्तान डेविड वॉर्नर ने अहम भूमिका निभाई। बेयरस्टो ने 97 और वॉर्नर ने 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इस अर्धशतक के साथ ही वॉर्नर IPL में 50 बार 50 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच में वॉर्नर ने 40 बॉल पर 52 रन बनाए। यह वॉर्नर के आईपीएल करियर की 46वीं हाफ सेंचुरी है। वॉर्नर ने आईपीएल करियर में अब तक 4 शतक भी लगाए हैं। इन चार शतक को छोड़ दें तो वॉर्नर ने IPL में अब तक 46 बार 50 से ज्यादा और 100 से कम रन बनाए हैं। वॉर्नर ने IPL में अब तक कुल 132 मैच खेले हैं। जिसमें उन्होंने 42.89 की एवरेज से 4933 रन बनाए हैं। वॉर्नर के बाद सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाली लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। कोहली ने अपने IPL करियर में अब तक 42 बार 50 प्लस रन बनाए हैं। इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 39 बार 50 प्लस रन बनाए हैं।

डेविड वॉर्नर ने कहा, राशिद ने काफी शानदार काम किया, वो विश्व स्तर के गेंदबाज

दुबई।

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीनज के 22वें मैच में को किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रनों से हराया। इस जीत में हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो के बीच हुई पहले विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी का अहम योगदान रहा। ऑस्ट्रेलिया के वॉर्नर ने 52 रन बनाए और बेयरस्टो ने 97 रन बनाए। मैच के बाद वॉर्नर ने कहा कि वो और बेयरस्टो एक साथ मजे से बल्लेबाजी करते हैं। वॉर्नर ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग सोचते हैं कि दो देशों (ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) के बीच नफरत है। यह अच्छा जा रहा है। मैं सिर्फ उन्हें स्ट्राइक दे रहा था। हम दोनों एक साथ बल्लेबाजी का लुत्फ लेते हैं। उन्होंने कहा, हमने गेंदबाजों पर आक्रामण करने का सोचा था और किया भी। हमने पावरप्ले में अच्छा किया। हमें राजस्थान के खिलाफ मुश्किल मैच खेलना है। उम्मीद है कि हम दोबारा 200 का स्कोर कर सकेंगे।

राशिद विश्व स्तर के गेंदबाज

पंजाब के लिए जब तक निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक उसकी जीत की उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन जैसे ही राशिद खान ने पूरन को आउट किया हैदराबाद की जीत महज औपचारिकता रह गई थी। उन्होंने कहा, जब निकोलस बल्लेबाजी कर रहे थे तब मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं उनके साथ बांग्लादेश में खेला हूं और जब वो मारते हैं तो काफी क्लीन मारते हैं। राशिद ने काफी शानदार काम किया। वो विश्व स्तर के गेंदबाज हैं। उनका टीम में रहना शानदार है।

भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज सम्मोहक होगी

डिजिटल डेस्क, सिडनी क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निक हॉक्ले इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि एसईएन विशेषज्ञ किस तरह से भारत के साथ होने वाली सम्मोहक टेस्ट सीरीज को कवर करते हैं। भारत को नवंबर से जनवरी तक आस्ट्रेलियाई दौरे पर चार टेस्ट मैच, तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया द्वारा जारी बयान में हॉक्ले ने कहा, हम स्पोर्टर्स इंटरटेनमेंट नेटवर्क (एसईएन) के साथ साझेदारी कर काफी खुश हैं। एसईएन पूरे देश में खेल का एक जाना-माना स्थान बना है और हम इस बात को देखना चाहते हैं कि उनके विशेषज्ञ किस तरह से भारत के खिलाफ होने वाली सम्मोहक सीरीज को कवर करते हैं। एसईएन के चीफ स्पोर्टस कॉलर जेरार्ड व्हाइटले कॉमेंट्री टीम की अध्यक्षता करेंगे और बाकी की टीम का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत 17 दिसंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को बचाने की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम को हालांकि बीसीसीआई और सीए द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है।

बॉर्डर बीसीसीआई के सामने झुकने को लेकर क्रिकेट आस्ट्रेलिया पर बरसे

नई दिल्ली।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने अभी तक भारत के खिलाफ होने वाले सीरीजों का कार्यक्रम जारी नहीं किया है, जो अगले महीने से शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले ही विवाद पैदा हो गया है। सिर्फ ब्रॉडकास्टर सेवन वेस्ट मीडिया ही नहीं, चैनल-7 के मालिक भी आस्ट्रेलिया द्वारा तैयार किए गए संभावित कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं। अब आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने भी सीए को आड़े हाथों लिया है और बीसीसीआई के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने पर उसकी आलोचना की है, खासकर सिडनी टेस्ट को लेकर। सिडनी टेस्ट आमतौर पर न्यू ईयर टेस्ट के तौर पर जाना जाता है जो जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होता है, मुख्यत~ तीन या चार जनवरी से। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच (26 से 30 दिसंबर) और न्यू ईयर (तीन से सात जनवरी) टेस्ट मैच के बीच गैप तीन दिन का होता है, लेकिन भारत एक सप्ताह से ज्यादा का गैप की मांग कर रही है। सीरीज का आखिरी टेस्ट 15 से 19 जनवरी के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाना है। ब्रिस्बेन टेस्ट 19 जनवरी को खत्म होगा इसलिए सीरीज आस्ट्रेलियन ओपन से टकराएगी जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होनी है। इस सीरीज पर बॉर्डर की नाराजगी इसलिए और महत्व रखती है क्योंकि सीरीज का नाम ही गावस्कर-बॉर्डर ट्रॉफी है। पूर्व कप्तान ने फॉक्स स्पोर्ट से कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे लेकर बहस होनी चाहिए। अगर यह जरूरी है वो भी वायरस के कारण तो यह ठीक है लेकिन यह इसलिए हो रहा क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और न्यू ईयर टेस्ट के बीच लंबा गैप चाहते हैं तो यह बकवास है। उन्होंने कहा, हम इसे वर्षों से कर रहे हैं। यह क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच ट्रीट का काम करता है। अगर यह सिर्फ इसलिए बदला जाता है क्योंकि भारत चाहता है तो मैं इससे खुश नहीं हूं। बॉर्डर ने कहा, मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिमागी खेल खेल रहे हैं। पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, वह अपने आप को विश्व क्रिकेट की ताकत समझते हैं और आर्थिक तौर पर भी, इसलिए उनका चीजों में हस्ताक्षेप रहता है। लेकिन अगर रोल पलट दिए जाएं तो हम ज्यादा कुछ इसमें नहीं कहेंगे। यह हमारे सामने रख दी जाएगी कि आपको इन तारीखों को खेलना है। उन्होंने कहा, आप चाहें जितना मोल-भाव कर लो लेकिन यह पारंपरित तारीखें हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। मैं नहीं झुकूंगा। हमारे पास पारंपरिक तारीखें हैं, उनके साथ बने रहिए।

बॉर्डर ने ब्रिस्बेन टेस्ट को शिफ्ट करने को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ब्रिस्बेन टेस्ट काफी वर्षों से हमारा पहला टेस्ट रहा है। यह शानदार मैदान है। यह वो पिच है जिसे हम जानते हैं और हम अच्छा खेलेंगे। यह हमारे इंटरनेशनल समर को बड़ी शुरुआत देते हैं। उन्होंने कहा, अब भारत पहला मैच ब्रिस्बेन में खेलना नहीं चाहता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए।

गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं यमनाम

नई दिल्ली। डिफेंडर बिकास यमनाम गार्जियन की अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले और इकलौते भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गार्जियन की इस 2020 सूची में दुनिया के 60 युवा प्रतिभाशाली फुटबाल खिलाड़ी शामिल होते हैं। गार्जियन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, गेंद के साथ धैर्य रखने वाला, खेल को अच्छे से पढ़ने वाला और तेज तथा लंबी थ्रो में महारत हासिल करने वाला, युवा ने अंतर्राष्ट्रीय टीम में काफी तेज प्रगति की है। उनकी प्रोफाइल में 2018 एशियाई अंडर-16 चैम्पियनशिप का प्रदर्शन शामिल है जहां भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। इस मैच में हालांकि वो दक्षिण कोरिया से 0-1 से हार गई थी। 17 साल के मणिपुर के डिफेंडर को इंडियन एरोज ने लोन पर लिया था। प्रोफाइल में लिखा था, उन्होंने इंडियन एरोज के साथ लोन पर खेलते हुए काफी प्रभावित किया था। इसके बाद वो पंजाब गए थे। उन्होंने कई बड़े भारतीय क्लबों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। मिनर्वा अकादमी एफसी के मालिक रंजीत बजाज ने कहा, यह काफी अच्छी खबर है और इससे मुझे बेहद खुशी मिली है। साथ ही गर्व भी हुआ है कि बिकास इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए गए हैं। उनमें काफी सारी प्रतिभा है, हर कोई उनकी तारीफ करता है। उनमें महान खिलाड़ी बनने के सारे गुण हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम-1' का किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को ट्वीट कर दी बधाई

नयी दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को नयी पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो भारतीय वायुसेना के रणनीतिक अस्त्र-शस्त्र भंडार में शामिल होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम-1 की गति मैक दो या ध्वनि की गति से दोगुनी है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल जब वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार होगी तो इसे सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल का परीक्षण प्रक्षेपण किया गया।

पूर्व सीबीआई प्रमुख की आत्महत्या पर बोली शिवसेना, किसी को संदिग्ध मौत की वजह जानने में रुचि नहीं

मुंबई। शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार के कथित 'आत्महत्या' से वह स्तब्ध है और उसे आश्चर्य है कि आखिर किसी को उनकी संदिग्ध मौत की वजह जानने में क्यों कोई रुचि नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में लिखा, ''यह अविश्वसनीय है कि कुमार जैसे व्यक्ति, जो न केवल सीबीआई के निदेशक थे और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे बल्कि सेवामुक्त होने के बाद नगालैंड और मणिपुर के राज्यपाल भी थे, अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। उन्होंने विशेष क्षमता के साथ विशेष रक्षा समूह (एसपीजी) में भी अपनी सेवाएं दी।'' गौरतलब है कि कुमार बुधवार को शिमला के अपने आवास पर फंदे से लटके हुए मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि 69 वर्षीय कुमार ने सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा कि वह नयी यात्रा पर जा रहे हैं। संपादकीय में लिखा गया कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी मानसिक और शारीरिक रूप में मजबूत थे और इसलिए दशकों के करियर में अहम जिम्मेदारी दी गई। मराठी में प्रकाशित सामना ने लिखा, ''ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है और कोई सवाल नहीं करता...यह आश्चर्यजनक है।''

चाईबासा केस में लालू यादव को मिली जमानत, अभी जेल में ही रहना होगा

नयी दिल्ली। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एक अन्य मामले में सजायाफ्ता होने कारण फिलहाल जेल में ही रहेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को जमानत के लिए 50-50 हजार के दो निजी मुचलके देने और दो लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा करने को कहा।

दिल्ली कैबिनेट ने वृक्षारोपण नीति और कनॉट प्लेस में 'स्मॉग टावर' लगाने को दी मंजूरी

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों के संरक्षण के लिए एक वृक्षारोपण नीति को मंजूरी दी। केजरीवाल ने एक आनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक 'स्मॉग टावर' लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 20 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और टावर का निर्माण 10 महीने में होगा। उन्होंने दावा किया कि यह दुनिया में अपने तरह का पहला टावर होगा। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण नीति के तहत संबंधित एजेंसियों को उनकी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले पेड़ों में से 80 प्रतिशत को नये स्थान पर लगाना होगा। केजरीवाल ने कहा कि नयी नीति के तहत सरकार द्वारा एक समर्पित वृक्षारोपण इकाई स्थापित की जाएगी।

लद्दाख 'भारत का गौरव', अ बनने के बाद से बड़े स्तर पर हुआ विकास: मुख्तार अब्बास नकवी

लेह। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख 'भारत का गौरव' है और पूरे देश को लेह तथा करगिल की जनता द्वारा दिखाई गयी देशभक्ति पर गर्व है। पर्वतीय परिषद के आगामी चुनाव के लिहाज से लेह-लद्दाख में चुशोत योकमा, चुशोत शमा, चुशोत गोंगमा, फयांग चुशगो और फयांग थंगनाक में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 'भारत के गौरव' की रक्षा के लिए तथा लेह-लद्दाख की जनता की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नकवी की जनसभाओं में क्षेत्र के दूर-दराज के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के कारण क्षेत्र को मिले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद लेह और लद्दाख की जनता के व्यापार, कृषि, रोजगार, संस्कृति, भूमि और संपत्ति से संबंधित अधिकारों को पूरी तरह संवैधानिक संरक्षण मिला है। नकवी ने कहा कि लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद बड़े स्तर पर विकास गतिविधियां संचालित हुई हैं और जनता, खासतौर पर लेह और करगिल के युवकों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने से अप्रचलित कानूनों के अवरोधक समाप्त हो गये हैं जिन्होंने लेह-लद्दाख में विकास प्रक्रिया को बाधित कर रखा था।

पीएम मोदी रविवार को संपत्ति कार्ड वितरण की करेंगे शुरुआत, पीएमओ ने दी जानकारी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'स्वामित्व' योजना की शुरुआत करेंगे।इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर उपलब्ध कराये जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। बयान के अनुसार महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिये कुछ राशि लिये जाने की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा। पीएमओ के बयान के अनुसार यह पहली बार है कि लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लाभ के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरूआत की थी। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। बयान के अनुसार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से चार साल (2020-24) में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांव आएंगे।

जमीन अतिक्रमण के आरोपों पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, संपत्ति 300 वर्षों से परिवार के पास

ग्वालियर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस जिन जमीनों पर अवैध कब्जे करने का उन पर आरोप लगा रही है, वे उनके परिवार के पास 300 वर्षों से हैं। उन्होंने कहा, ''अब मेरी पैदाइश राजपरिवार में हुई तो इस गलती को मैं स्वीकार सकता हूं, लेकिन वो लोग इसका जबाव दें, जो नए महाराजा बन गए हैं।'' मध्य प्रदेश में

विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिये तीन नवंबर को मतदान होना है इनमें से अधिकांश सीटें ग्वालियर और चंबल संभाग में हैं। इन दिनों इलाके के दौरे पर आये सिंधिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, '' कांग्रेस के वे नेता जमीनों पर कब्जे के आरोप लगा रहे हैं, जो नए-नए महाराजा बने हैं। जिन जमीनों पर वे कब्जे की बात करते हैं, वे तो 300 वर्षों से मेरे परिवार के पास हैं। अब इस परिवार में पैदाइश होना गलत है, तो मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं। मेरा एजेंडा एक ही है, जनता का विकास और प्रगति।'' उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की नहीं, बल्कि जनता के विकास व उज्ज्वल भविष्य की चिंता करते हैं और इसी एकमात्र लक्ष्य को लेकर राजनीति में हैं। सिंधिया ने कहा, ''इन पांच महीनों के दौरान मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कोशिश की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक विकास कार्य जरूर हो। कांग्रेस के 15 महीने का कुशासन और पांच महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शासन सभी ने देखा है।'' उन्होंने कहा कि वे विकास के लिए जाति या पंथ देखकर काम नहीं करते, क्योंकि उनके लिए मतदाता और जनता भगवान हैं और हर तरीके से विकास उन तक पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि सिंधिया ने अवैध तरीके से ग्वालियर सहित कई शहरों में जमीनों पर कब्जा किया है। ग्वालियर में भी कांग्रेस लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रही है।

भारत अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, जयशंकर ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला को दिया आश्वासन

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफगान शांति के वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को आश्वासन दिया कि भारत अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर और अब्दुल्ला ने अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के विभिन्न पहलुओं और द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया, ''एचसीएनआर चेयरमैन डा. अब्दुल्ला से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक अच्छी चर्चा हुई। हाल के घटनाक्रमों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण का स्वागत किया। भारत एक पड़ोसी के रूप में अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।''

अब्दुल्ला ने कहा कि विदेश मंत्री ने उन्हें अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत के ''पूर्ण सहयोग'' का आश्वासन दिया। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ''भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर हमेशा की तरह प्रसन्नता हुई। हमने अफगान शांति प्रक्रिया, द्विपक्षीय संबंधों और शांति प्रयायों के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का मुझे आश्वासन दिया।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक बैठक में 'राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद' (एचसीएनआर) के चेयरमैन अब्दुल्ला से कहा था कि भारत शांति की चाह रखने वाले अफगानिस्तान के लोगों और उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं का हमेशा समर्थन करेगा। अब्दुल्ला एक क्षेत्रीय आम सहमति बनाने और अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन के प्रयासों के तहत मंगलवार को पांच दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे थे।

एक प्रभावशाली अफगान नेता की भारत यात्रा अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में शांति वार्ता के बीच हो रही है। तालिबान और अफगान सरकार 19 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत कर रहे हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में भारत एक प्रमुख हितधारक रहा है। भारत इस देश में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में दो अरब अमरीकी डालर का पहले ही निवेश कर चुका है। भारत अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित एक राष्ट्रीय शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है।

कांग्रेस ने गुजरात उपचुनाव में किया जीत का दावा, कहा- जनता भाजपा सरकार से हो चुकी है तंग

अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में तीन नवंबर को आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करेगी क्योंकि जनता राज्य की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। जन आक्रोश रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सातव ने कहा कि राज्य में भाजपा पिछले 25 वर्षों से सत्ता में रही लेकिन किसानों और युवाओं समेत समाज के सभी वर्ग नाखुश हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सभी वर्गों ने यह महसूस किया है कि भगवा दल को वोट देना ऐसी भ्रष्टाचारी सत्ता को समर्थन देना है जोकि बांटो और शासन करो में भरोसा करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का जन आंदोलन राज्य के उपचुनाव से शुरू होगा और स्थानीय निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा (जोकि नवंबर के अंत अथवा दिसंबर के लिए प्रस्तावित है)। लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनाणी ने रैली को संबोधित करते हुए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार पर लॉकडाउन के दौरान जनता पर आर्थिक मार पड़ने के बावजूद स्कूलों और कॉलेजों की फीस माफ नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि फरवरी में अहमदाबाद के एक स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप के कारण भारी भीड़ जुटना ही गुजरात में कोरोना वायरस के प्रसार की वजह बना।

राजस्थान में पुजारी को जलाने के मामले में भाजपा ने साधा निशाना, कहा- गहलोत का इस्तीफा लें राहुल गांधी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

राजस्थान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनकी सरकार को ''सुधारने'' की कवायद करनी चाहिए। राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में एक पुजारी को कथित तौर पर आग लगा दी गयी। इसके बाद एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ''बेहद ही गंभीर'' मामला बताते हुए राज्य सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए।''

केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज पुजारी की जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले ही राज्य के बहरोड़ पुलिस थाने पर एके-47 हमले में अपराधियों को छुड़ा ले जाने की घटना हुई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है।'' राजस्थान में हाल के दिनों में हुई बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर राजस्थान की

सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा, ''राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी 'भारत दर्शन' की बजाए राजस्थान के जिले-जिले में जाना चाहिए। वह वहां अपनी सरकार से या तो इस्तीफा ले लें, या सुधारने के लिए कवायद करें।'' उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि वह (राहुल) कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे? उन्होंने कहा, ''उनकी यह राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।'' जावड़ेकर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह दी कि वे अपने कार्यकर्ताओं को राजस्थान के उन स्थानों पर भेजें जहां बलात्कार की घटनाएं हुई हैं ताकि वे पीड़ित पक्ष की आवाज उठाएं और कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को बाध्य करें।

वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में आगे है दिल्ली, पड़ोसी राज्य अभी भी गंभीर नहीं: गोपाल राय

नयी दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है, किंतु पड़ोसी राज्य इस बारे में अब भी गंभीर नहीं हैं जबकि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर होने की आशंका है। राय ने कहा कि आप सरकार वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अन्य राज्यों के साथ सहयोग चाहती है, टकराव नहीं। उन्होंने कहा, 'भूमि राज्यों में बंट गयी है लेकिन आकाश एक ही है।' राय ने कहा कि पराली जलाने के समाधान के तौर पर 'पूसा बायो-डिकंपोजर' पहल हरियाणा और पंजाब को और फायदा पहुंचाएगी तथा दिल्ली को यह लाभ मिलेगा कि उसे खेतों से निकलने वाले उस धुएं से छुटकारा मिल जाएगा जो हर साल शहर को गैस चैंबर बना देता है। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना शुरू हो गया है जिससे दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता का स्तर 'खराब' होने के बीच उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत काम कर रही एक इकाई ने बृहस्पतिवार को 15 अक्टूबर से क्रमिक प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना

हाथरस के बहाने जयंत चौधरी का मास्टरस्ट्रोक, महापंचायत कर जाटों को एकजुट करने का किया प्रयास

लखनऊ। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हुए बर्बर लाठीचार्ज को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मायी हुई है। जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ महापंचायत रैली कर जाट समुदाय का स्वाभिमान जगाने का दांव चला है। महापंचायत में जाट समुदाय के साथ जुड़े दूसरे दलों से जुड़े कई सियासी दिग्गज भी पहुंचे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयंत चौधरी के साथ हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जाट समुदाय के नेता खड़े नजर आए। लोकतंत्र बचाओ महापंचायत रैली की जो तस्वीर सामने आई उससे यह तो पता चलता है कि सियासी तौर पर दिल मिले न मिले लेकिन एकजुटता का संदेश तो दे ही दिया।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाथरस में जयंत चौधरी पर पुलिस द्वारा बरसाई गई लाठियां और लोकतंत्र बचाओ महापंचायत कर जयंत चौधरी ने भावनात्मक तौर पर जाटों को एकजुट करने का प्रयास किया और वह तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। यदि एकजुटता ऐसे ही कायम रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

लोकतंत्र बचाओ महापंचायत रैली कर आरएलडी ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करने की प्रक्रिया में पहला कदम रख दिया है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जहां जाट समुदाय के लोगों ने आरएलडी का साथ छोड़कर भाजपा की तरफ अपना रुख मोड़ा तो अजित सिंह और जयंत चौधरी का खासा नुकसान हुआ और वह साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भी हार गए। इसके अलावा विधानसभा 2012 की तुलना में 2017 में वोट शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। भले ही जयंत चौधरी दो लोकसभा चुनाव हार गए हों लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वह चौधरी चरण सिंह की विरासत को वापस मजबूत करने में जुट गए। जानकारों का मानना है कि आज भी जाट समुदाय का एक तबका जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है। ऐसे में उनके पास पार्टी को फिर से खड़ा करने का अवसर है।

हाथरस में हुई घटना के बाद जयंत चौधरी को जाट स्वाभिमान को मुद्दा बनाने का मौका मिल गया। रैली में मौजूद ज्यादातर लोगों ने कहा कि जाट समाज के मान-सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साफ कर दिया किसानों की आवाज को भी नहीं दबाया जा सकता है।

इस दौरान जाट नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार को चेताते हुए कहा कि लाठीचार्ज करके किसानों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। इसके साथ ही जाट नेताओं ने 'हम साथ-साथ हैं' का संदेश दिया और चुनाव में प्रदेश सरकार को सबक सिखाने की बात भी कही।

असम सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी सरकारी मदरसों को किया जाएगा बंद

गुवाहाटी। (एजेंसी)।

असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोनोवाल सरकार में मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ऐलान किया कि प्रदेश के सभी सरकारी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जनता के पैसों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सभी सरकारी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। सरमा ने कहा कि इस आदेश को लेकर अगले महीने एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही सरकारी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। सरमा ने कहा कि किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान को सरकारी धन से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम नवंबर में एक अधिसूचना जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम निजी तौर पर चलने वाले मदरसों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

सत्ता में आने पर फैसला पलट देंगे

असम सरकार के फैसले से एआईयूडीएफ सुप्रीमो और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सरकारी मदरसों को बंद कर देती है तो उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद उन्हें फिर से खोल देगी। बता दें कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान कर दिया कि प्रदेश में सरकार बनाने के बाद सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले को पलट दिया जाएगा।

फरवरी में हेमंत विश्व सरमा ने कहा था कि हमने सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य धार्मिक संस्थानों को फंड नहीं दे सकते। हालांकि, गैर सरकारी संगठनों/ सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित मदरसे जारी रहेंगे।

बाद में सरमा ने सफाई देते हुए कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी पैसों को खर्च नहीं किया जा सकता है। हालांकि, गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा कि संस्कृत की शिक्षा का मामला अलग है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम में 614 सरकारी तो 900 निजी मदरसे हैं और लगभग सभी मदरसों को जमीयत उलमा द्वारा चलाया जाता है। वहीं, प्रदेश में 100 सरकारी और 500 निजी संस्कृत संस्थान हैं। बता दें कि सरकार मदरसों पर हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है जबकि संस्कृत संस्थानों में हर साल महज 1 करोड़ रुपए खर्च होता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोरोना वैक्सीनः चीन ने दोस्ती दिखा कर बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका

इंटरनेशनल डेस्क:

चीन को अमेरिका और बांग्लादेश की निकटता चीन को रास नहीं आ रही है। बांगलादेश के अमेरिका के साथ ओपन स्काई संधि करते चीन भड़क गया और अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही दोस्त बांग्लादेश के साथ स्ट्रैजिक पॉर्टनरशिप को नई ऊंचाईयों तक ले जाने की बात करने वाले चीन ने मंगलवार को अपनी सिनोवेक कंपनी को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में बंद करने का आदेश दे दिया है। चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी अधिकारियों से कहा है कि अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने देश में करना है तो उन्हें इसकी फंडिंग करनी होगी।बांग्लादेश के स्वास्थ्य सचिव अब्दुल मन्नान ने बताया कि सिनोवेक कंपनी ने कहा है कि हम फिर से आपके देश में वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर सकते हैं लेकिन, इसके लिए आपको फंडिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिनोवेक पर निर्भर नहीं है। सरकार वैक्सीन विकसित होने के बाद अन्य सभी विकल्प तलाश रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीनी कंपनी सिनोवेक ने जो चिट्ठी बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है उसमें फंडिंग की मात्रा को नहीं बताया है। इस कंपनी की साइट पर भी अब वैक्सीन के बांग्लादेश में ट्रायल को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि सिनोवेक ने कोरोनावेक नाम से एक वैक्सीन बनाई है जिसका क्लिनिकल ट्रायल कई देशों में चल रहा है।

दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए आगे आया चीन, 'कोवैक्स' का बना हिस्सा

इंटरनेशनल डेस्क।

चीन ने शुक्रवार को बताया कि वह कोविड-19 के टीके संबंधी गठबंधन 'कोवैक्स' में शामिल हो गया है। चीन में कोरोना वायरस के टीके के तीन उम्मीदवार क्लीनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश ने गठबंधन का सह-नेतृत्व कर रहे 'गावी' के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। शुरुआत में, चीन गठबंधन में शामिल होने पर सहमत नहीं था।

वह गठबंधन में शामिल होने की अंतिम सीमा तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक बयान में कहा कि हम खासकर विकासशील देशों को टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और सक्षम देश कोवैक्स से जुड़ेंगे एवं इसे समर्थन देंगे। समझौते की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं और यह भी जानकारी नहीं है कि चीन इसमें कैसे योगदान देगा। इससे पहले, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि चीन विश्व के लोगों की भलाई के लिए टीका बनाएगा। इस गठबंधन को इसलिए बनाया गया है, ताकि अमीर देश संभावित टीका खरीदने पर सहमत हों और गरीब देशों तक इसे मुहैया कराने में मदद करे। अमेरिका ने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

गांधी जयंती पर भारत से मिलीं 40 से ज्यादा एंबुलेंस और स्कूल बस, नेपाल ने जताया आभार

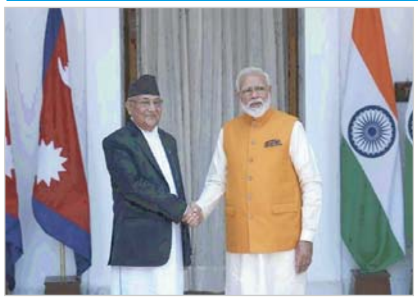

नेशनल डेस्क:

भारत ने 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर नेपाल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 41 एम्बुलेंस और छह स्कूल बसें दान की थीं। नेपाल ने भारत की इस दरियादिली और मदद पर खुशी जाहिर की है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एक बयान के अनुसार वाहन 30 जिलों में काम करने वाले संगठनों को मुहैया कराये गए। भारत ने 1994 से करीब 823 एंबुलेंस उपहार में दिए हैं जिसमें गांधी जयंती पर दिए गए वाहन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि हालांकि इस बार दूतावास ने तीन अलग अलग श्रेणी की एंबुलेंस उपहार में दी हैं जिसमें उन्नत जीवन रक्षक श्रेणी, मूल जीवन रक्षक और साझा जीवन रक्षक एंबुलेंस शामिल हैं। तीनों श्रेणी की एंबुलेंस का निर्माण नेपाल सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। ये सुविधाएं वहां के 29 जिलों में काम कर रहे एनजीओ को मिली हैं। इन संगठनों ने मदद के लिए भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। बता दें कि इससे पहले भारत ने इस साल 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेपाल के विभिन्न अस्पतालों और धर्मार्थ संगठनों को 30 एम्बुलेंस सहित 36 वाहन दान किए थे। इस अवसर पर यहां स्थित भारतीय दूतावास ने देशभर में फैले 51 पुस्तकालयों और शैक्षणिक संस्थानों को किताबें भी भेंट की थीं।

भारत के बाद पाकिस्तान ने भी दिया चीन को झटका, अश्लील कंटेट को लेकर Tik-Tok पर लगाया बैन

इस्लामाबाद। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी चीन को झटका देते हुए टिक-टॉक को बैन करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण का कहना है कि कंपनी अवैध ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र के विकास के निर्देशों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रही है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण की ओर से जारी बयान में कहा गया कि, टिक-टॉक को कई बार अनैतिक और असभ्य सामग्री को ब्लॉक करने के लिए कहा गया लेकिन टिक-टॉक पाकिस्तानी अथॉरिटी को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद दूरसंचार प्राधिकरण ने पाकिस्तान में टिक-टॉक ब्लॉक करने का फैसला किया। बयान में कहा गया कि बीते जुलाई में ही पाकिस्तान ने टिकटॉक को चेतावनी दी थी। फैसले के बारे में एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि बार-बार अनैतिक और असभ्य कॉन्टेंट को ब्लॉक करने के लिए प्रक्रिया तैयार करने के लिए कहा जा रहा था लेकिन प्लैटफॉर्म पाकिस्तानी अथॉरिटी को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद पाकिस्तान में टिक-टॉक ब्लॉक करने का फैसला किया गया। जुलाई में ही पाकिसतान ने टिकटॉक को इसके लिए चेतावनी दी थी। पिछले दिनों पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने द न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हालांकि, इमरान खान की चिंता डेटा सिक्यॉरिटी नहीं, बल्कि देश में फैल रही अश्लीलता है और इसकी वजह से वह टिकटॉक सहित इस तरह के अन्य ऐप को भी बैन करने पर विचार कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

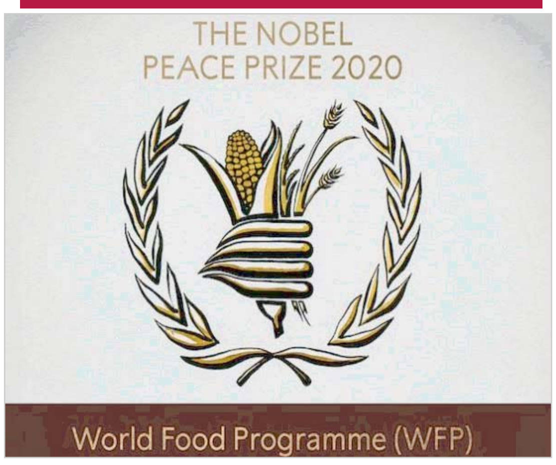

World Food Program को मिला शांति नोबेल पुरस्कार, भूख के खिलाफ दुनियाभर में छेड़ी जंग

इंटरनशनल डेस्कः साल 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार से विश्व खाद्य कार्यक्रम (**World Food Program**) को सम्मानित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र (**United Nations**) के कार्यक्रम को शुक्रवार को यह सम्मान देने की घोषणा की गई। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रेइस एंडरसन ने की। नोबेल समिति ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनियाभर में भूखे लोगों की संख्या में लाखों का इजाफा हुआ है। समिति ने सरकारों से आह्वान किया कि वे **World Food Program** और अन्य सहायता संगठनों को वित्तीय मदद सुनिश्चित करे ताकि वे उन्हें भोजन मुहैया करा सकें। बता दें कि **World Food Program** साल 1961 से दुनियाभर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। **WFP** यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा के जरिए देशों की आबादी को मूलभूत ताकत और सुविधाएं दी जा सके।**WFP** दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर काम करता है। साल 2019 में **WFP** ने 88 देशों में 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया। **WFP** ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भूख को हथियार बनाने के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया है.

न्यायाधीश और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रिहायशी या वाणिज्यिक भूखंड लेने के हकदार नहीं: न्यायाधीश

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा है कि देश के न्यायाधीश और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी न तो संविधान और न ही किसी कानून के तहत आवासीय या वाणिज्यिक भूखंड पाने के हकदार हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह बात कही गई है। न्यायमूर्ति काजी फाइज ईसा ने बृहस्पतिवार को चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास परियोजना के वास्ते भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले में चार न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत निर्णय सुनाए जाने के अतिरिक्त यह टिप्पणी की। समाचार पत्र द 'डॉन' की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति ईसा ने कहा कि संविधान और कानून (राष्ट्रपतीय आदेश) के तहत बड़ी अदालतों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भूखंड हासिल करने के हकदार नहीं है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, ' सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सदस्यों को भूखंड और कृषि भूमि मिलती है और रैंक बढ़ने पर उन्हें अतिरिक्त भूखंड और कृषि भूमि दी जाती है।' ईसा ने कहा कि वे न तो संविधान और न ही कानून के तहत रिहायशी या वाणिज्यिक भूमि पाने के हकदार हैं।

ईरान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा करेंगे

बीजिंग, चीन ने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा में कहा कि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ अपने चीनी समकक्ष वांग यी के आमंत्रण पर इस यात्रा पर आ रहे हैं। इस घोषणा के एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हुए उसके लगभग सभी वित्तीय क्षेत्रों को काली सूची में डाल दिया था। चीन ईरान का सहयोगी और 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में एक पक्ष रहा है। इस समझौते से अमेरिका ने अपने हाथ खींचते हुए ईरान पर पाबंदियां लगा दी थीं। बृहस्पतिवार को अमेरिका की काली सूची के दायरे में ईरान के 18 बैंक भी आ गए हैं। ऐसे में इन बैंकों के साथ लेनदेन करने वाले विदेशी, गैर-ईरानी वित्तीय संस्थानों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इन पाबंदियों के चलते ईरानी बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से कट जाएंगे। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने इन पाबंदियों का विरोध किया है। जरीफ ने कहा है कि वैश्विक संकट के दौरान अमेरिका का यह कदम ''मानवता के खिलाफ अपराध'' है।

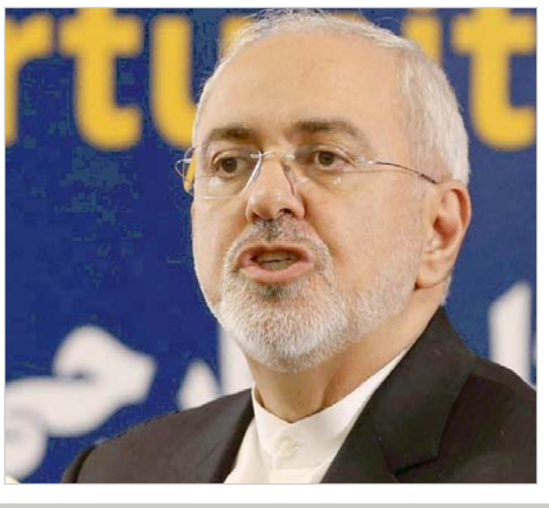

कोरोना वायरस मानव त्वचा पर नौ घंटे तक रह सकता है जीवितः अध्ययन

नयी दिल्ली,

एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस मानव त्वचा पर नौ घंटे तक जीवित रह सकता है। यह बात एक अध्ययन में सामने आयी है। एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस से ही कोविड-19 होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इन्फ्लूएंजा ए वायरस (आईएवी) मानव त्वचा पर दो घंटे जीवित रह सकता है। इन अनुसंधानकर्ताओं में जापान स्थित क्योतो प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी आफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। यह अध्ययन पत्रिका 'क्लिनिकल इंफेक्शस डिजीज' में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में यह बात भी सामने आयी कि दोनों ही वायरस हैंड सेनेटाइजर से निष्क्रिय हो जाते हैं। यह निष्कर्ष कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने या सेनेटाइजर का उपयोग करने के महत्व को रेखांकित करता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पत्रिका में लिखा है, ''एसएआरएस-सीओवी-2 के मानव त्वचा पर नौ घंटे तक जीवित रहने से आईएवी की तुलना में संपर्क संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है।'' उन्होंने कहा, ''एसएआरएस-सीओवी-2 संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए हाथ की उचित स्वच्छता जरूरी है।''

दुनियाभर में कोरोना फैलाने वाले चीन की करतूतों को नजरअंदाज कर दोस्ती निभा रहा पाकिस्तान

इस्लामाबाद।

दुनियाभर में कोरोना महामारी के फैलने के बाद चीन का कई महीनों से भारत के साथ लद्दाख में तनावपूर्ण माहौल है। सिर्फ कोरोना, लद्दाख पर ही नहीं, बल्कि चीन शिनजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उससे भी दुनिया के निशाने पर आ गया है। लेकिन, चीन की इन करतूतों को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसकी चीन के साथ हमेशा दोस्ती बनी रहे। एक लेख के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन पर अपनी आलोचना को संतुलित किया है क्योंकि पाकिस्तान को बेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से अरबों डॉलर का निवेश प्राप्त होता है। चीन-पाकिस्तान के रिश्तों को फलते-फूलते रहने के लिए, इमरान खान ने कोरोना वायरस के शुरुआती चरणों को भी चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में वास्तविकता से कम आंका था। इमरान खान ने फरवरी में किए एक ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान चीन के लोगों और उसकी सरकार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा हुआ है और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। लेख में उजागर किया है कि खान ने चीनी सरकार द्वारा शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर ढाये जा रहे जुल्मों की भी अनदेखी की और अपनी आंखों को बंद रखना बेहतर समझा। लेखक ने कहा, पिछले साल, खान ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार पर ध्यान नहीं दिया, चीन के विवादित हॉन्ग-कॉन्ग सिक्योरिटी बिल का समर्थन किया और अब चीन के कोरोना वायरस पर उसके साथ खड़ा हुआ। इसके पीछे चीन द्वारा पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर में 60 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करना भी बड़ी वजह बताया जा रहा है।

जयशंकर ने अफगानिस्तानी नेता अब्दुल्ला से की मुलाकात, शांति के लिए पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

नई दिल्ली:

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफगान शांति के वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को आश्वासन दिया कि भारत अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर और अब्दुल्ला ने अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के विभिन्न पहलुओं और द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया, ''एचसीएनआर चेयरमैन डा. अब्दुल्ला से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक अच्छी चर्चा हुई। हाल के घटनाक्रमों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण का स्वागत किया। भारत एक पड़ोसी के रूप में अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।' अब्दुल्ला ने कहा कि विदेश मंत्री ने उन्हें अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत के ''पूर्ण सहयोग' का आश्वासन दिया। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ''भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर हमेशा की तरह प्रसन्नता हुई। हमने अफगान शांति प्रक्रिया, द्विपक्षीय संबंधों और शांति प्रयायों के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का मुझे आश्वासन दिया।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक बैठक में 'राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद' (एचसीएनआर) के चेयरमैन अब्दुल्ला से कहा था कि भारत शांति की चाह रखने वाले अफगानिस्तान के लोगों और उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं का हमेशा समर्थन करेगा। अब्दुल्ला एक क्षेत्रीय आम सहमति बनाने और अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन के प्रयासों के तहत मंगलवार को पांच दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे थे। एक प्रभावशाली अफगान नेता की भारत यात्रा अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में शांति वार्ता के बीच हो रही है। तालिबान और अफगान सरकार 19 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत कर रहे हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में भारत एक प्रमुख हितधारक रहा है। भारत इस देश में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में दो अरब अमरीकी डालर का पहले ही निवेश कर चुका है। भारत अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित एक राष्ट्रीय शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है।

ट्रम्प की हैरिस पर की गई टिप्पणी ''निंदनीय'', ''राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ'' : बाइडेन

वाशिंगटन,

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उनकी पार्टी की उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर की गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणी को ''निंदनीय'' और ''राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ'' बताया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस के बीच बुधवार को आधिकारिक बहस हुई थी, जिसमें ट्रम्प के कोविड-19 स्थिति से निपटने, नौकरी, चीन, नस्लीय तनाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद ट्रम्प ने बृहस्पतिवार को 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार में हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर बाइडेन तीन नवम्बर को चुनाव जीत गए तो एक महीने के अंदर हैरिस उनकी जगह राष्ट्रपति बन जाएंगी। उन्होंने कहा था, '' वह कम्युनिस्ट हैं। वह समाजवादी नहीं हैं। आप उनकी सोच देखिए। वह हत्यारों और बलात्कारियों के लिए देश की सीमा खोलनी चाहती हैं।'' ट्रम्प की इस टिप्पणी के कुछ घंटे बाद बाइडेन ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी लोग उनकी इन बातों से थक गए हैं। बाइडेन ने एरिजोना में पत्रकारों से कहा, '' यह निंदनीय है, राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ है और अमेरिकी लोग अब इन बातों से परेशान हो गए हैं। उन्हें पता है कि यह शख्स कैसा है और इसे रोकना होगा।'' इस दौरान हैरिस भी बाइडेन के साथ मौजूद थी।

कोरोना वायरस से डरे चीन की निकली हेकड़ी, अमरीका से मदद लेने को हुआ तैयार

वाशिंगटन।

विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) से होने वाली मौतों की संख्या 10.62 लाख के पार पहुंच गयी है, जबकि 3.65 करोड़ से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में 3,65,27,341 लोग संक्रमित हो चुके है तथा अब तक 10,62, 075 लोगों की मौत हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में संक्रमण से लगभग 2.13 लाख लोगों की मौत हो चुकी है तथा अब तक 76.07 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 70,496 नये मामले दर्ज किये गये हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 69,06,152 हो गयी है। देश में इस समय कोरोना के कुल 8,93,592 सक्रिय मामले हैं जबकि अब तक 59,06,069 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या अब 50.28 लाख से अधिक हो गयी है, जबकि करीब1.49 लाख लोगों मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग 12.66 लाख हो गई है तथा 22,137 लोगों ने जान गंवाई है। कोलंबिया में इस जानलेवा विषाणु से अब तक करीब 8.86 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा 27,180 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं अर्जेंटीना में कोविड-19 से अब तक 8.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा 22,170 लोगों ने जान गंवाई है। स्पेन में इस प्राण घातक वायरस की चपेट में अब तक 8.48 लाख से ज्यादा लोग आए हैं तथा 32,688 लोगों ने जान गंवाई है। पेरू में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहां इस वायरस से अब तक लगभग 8.36 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 33,009 लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 8.04 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं तथा 83,096 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्रांस में इसकी चपेट में अब तक करीब 7.12 लाख लोग आए हैं तथा 32,539 लोगों की मृत्यु हुई है। दक्षिण अफ्रीका में 6.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा 17,704 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक लगभग 5.65 लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 42,682 लोगों की मौत हुई है। ईरान में इस महामारी से 4.88 लाख लोग संक्रमित है जबकि 27,888 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में कोरोना से 4.76 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा 13.167 लोगों की मौत हुई है। वहीं इराक में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 3.95 लाख हो गयी है, वहीं 9,683 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगलादेश में संक्रमितों की संख्या लगभग 3.75 लाख हो गई है तथा 5460 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस जानलेवा विषाणु से 3.38 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 36,083 लोगों की मौत हुई है। सऊदी अरब में कोरोना के 3.38 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं जबकि 4,971 लोगों की मौत हो चुकी हैं। फिलीपींस से कोरोना में अब तक लगभग 3.35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा 6152 लोगों की मौत हुई है। वहीं तुर्की में इस महामारी से अब तक लगभग 3.31लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 8,667 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया में संक्रमितों की संख्या करीब 3.21लाख हो गयी है तथा 11,580लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक लगभग 3.18 लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 6,552 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में अब तक इस वायरस की चपेट में अब तक 3.16 लाख से अधिक लोग आए हैं तथा 9,594 लोगों की मौत हुई है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

करें केले की उन्नत खेती

केला दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसमें पोषक तत्व अधिक होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए फायदे मंद है और इसीलिए इसकी हर सीजन चाहे गर्मी हो या हो सर्दी तासीर में ठण्डा होने के कारण हर मौसम में यह खूब बिकता है। इससे बनने वाले तरह-तरह की रेसिपी बनाई जाने लगी है। केले के चिप्स तो हर आम आदमी को पसंद आते हैं। यही कारण है कि अकेले भारत में ही केले की खेती तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर में होती है। इसकी खेती करने वाले किसान आर्थिक स्थिति भी सुधरी है।

विश्व भर में केला एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत में लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है जिससे 180 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के कुल केला क्षेत्र का 70 फीसदी अकेले जलगांव जिले में है। देशभर के कुल केला उत्पादन का लगभग 24 फीसदी भाग जलगांव जिले से प्राप्त होता है। केले को गरीबों का फल कहा जाता है। केले का पोषक मान अधिक होने के कारण केरल राज्य एवं युगांडा जैसे देशों में केला प्रमुख खाद्य फल है। केले के उत्पादों की बढती मांग के कारण केले की खेती का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

केला उत्पाद निम्न है केला चिप्स, केला फिग, केला आटा, केला पापड, केला हलवा, केला जूस, केला पल्प, केला फल केनिंग, केला टाफी, केला मदिरा, केला शेम्पेन इत्यादि सामग्रियां तेयार की जाती हैं।

जलवायुः केला उत्पादन के लिये उष्ण तथा आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। जहाँ पर तापर्क्रम 20-35 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है वहाँ पर केले की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। वार्षिक वर्षा 150-200 से.मी. समान रूप से वितरित होना चाहिये। शीत एवं शुष्क जलवायु में भी इसका उत्पादन होता है। परंतु पाला एवं गर्म हवाओं (लू) आदि से काफी क्षति होती है।

भूमिः केले की खेती के लिए बलुई से मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। जिसका पी. एच मान 6.5-7.5 एवं उचित जल निकास का होना आवश्यक हैं। केले की खेती अधिक अम्लीय एवं क्षारीय भूमि में नही की जा सकती है। भूमि का जलस्तर 7-8 फीट नीचे होना चाहिये।

केले की व्यवसायिक प्रजातिया:

(1) ड्वार्फ केवेन्डिस (भुसावली, बसराई, मारिसस, काबुली, सिन्दुरानी, सिंगापुरी जहाजी, मोरिस) यह प्रजाति म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एवं कर्नाटक की जलवायु के लिये बहुत उपयुक्त पायी गयी है। इस प्रजाति से चयन कर गनदेवी सिलेक्शन (हनुमान) अथवा पाडर्से नाम की जातियां विकसित की गई हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 20-25 कि. ग्रा. प्रति पौधा है। इस प्रजाति का पौधा बोना किस्म का 1.5 - 1.8 मीटर ऊंचा होता है फल बडे, मटमैले पीले या हरेपन लिये हुये पीला होता है। तना मौटा हरा पीलापन लिये हुये होता है। पत्तियां चौड़ी एवं पीली होती हैं औसतन 9-10 हेण्ड प्रति बंच (गुच्छा) होता है। औसत फिंगर की लग्बाई 20 सें.मी. एवं मोटाई 10 से.मी. होती है।

(2) रोबस्टा (एएए) इसे बाम्बेग्रीन, हरीछाल, बोजीहाजी आदि नामो से अलग अलग प्रांतो मे उगाया जाता है इस प्रजाति को पश्चिमी दीप समूह से लगाया गया है। पौधों की ऊंचाई 3-4 मीटर, तना माध्यम मोटाई हरे रंग का होता है। प्रति पौधे मे 10-19 हेण्ड्स मे फर्टाइल पुष्प होते हैं जिनमें हरे रंग की फिंगर विकसित होती है । बंच का वजन औसतन 25-30 किलो ग्राम होता है। फल अधिक मीठे एवं आकर्षक होते हैं। फल पकने पर चमकीले पीले रंग का हो जाता है। यह प्रजाति सिंगाटोक (लीफ स्पॉट) बीमारी से काफी प्रभावित होती है। फलों की भंडारण क्षमता कम होती है।

(3) रस्थली (सिल्क एएबी)- इस प्रजाति को मालभोग अमृत पानी सोनकेला रसवाले आदि नामों से विभिन्न राज्यों मे व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है पौधे की ऊंचाई 2.5-3.0 मीटर होती है पुष्पन 12-14 माह के बाद ही प्रारंभ होता है। फल (फिंगर) चार कोण बाले हरे, पीले रगं के मोटे होते हैं। छिलके पतला होते है जो पकने के बाद सुनहरे पीले रगं के हो जाते हैं। केले का बंच 15 से 20 किलोग्राम का होता है। फल अधिक स्वादिष्ट सुगन्ध पके सेब जैसी कुछ मिठास लिये हुये होता है। केले का छिलका कागज की तरह पतला होता है इस प्रजाति की भण्डारण क्षमता कम होती है।

(4) पूवन (एबी) = इसे चीनी चम्पा, लाल वेल्ची और कदली कोडन के नाम से जाना जाता है इसका पौघा बेलनकार मध्यम ऊंचाई का 2.25 - 2.75 मीटर होता है। रोपण के 9-10 महीने में पुष्पण प्रारंभ हो जाता है। इसमें 10-12 हेण्डस रहते हैं। प्रत्येक हेंड में 14-16 फिंगर आती है, फल छोटे बेलनाकार एवं उभरी चोंच वाले होते हैं। फल का गूदा हाथी के दांत के समान सफेद एवं ठोस होता है। इसे अधिक समय तक भण्डारित किया जा सकता है। फल पकने के बाद भी टूटकर बंच से अलग नहीं होते।

(5) करपूरावल्ली (एबीबी) = इसे बोन्था, बेन्सा एवं केशकाल आदि नामों से जाना जाता है। यह किस्म किचन गार्डन में लगाने लिए उपयुक्त पायी गयी है। इसका पौधा 10-12 फीट लम्बा होता है। तना काफी मजबूत होता है। फल गुच्छे में लगते है। फल पर तीन रिंज (उभार) होते हैं। एक पौधे में 5-6 पंजे बनते हैं जिसमें 60-70 फल होते हैं। इनका वजन 18-20 कि. ग्राम. होता है। फल मोटे नुकीले और हरे पीले रंग के होते हैं। यह चिप्स एवं पाउडर बनाने के लिये सबसे उपयुक्त प्रजाति है।

(6) नेन्द्रन (प्लान्टेन एएबी) = इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई है। इसे सब्जी केला या रजेली भी कहते हैं। इसका उपयोग चिप्स बनाने में सर्वाधिक होता है। इसका पौधा बेलनाकार मध्यम मोटा तथा 3 मीटर ऊंचाई वाला होता है। गुच्छे में 4-6 हेण्डस और प्रत्येक हेण्ड में 8-14 फिंगर होती हैं। फल 20 से.मी. लम्बा, छाल मोटी तथा थोड़ा मुड़ा एवं त्रिकोणी होता है। जब फल कच्चा होता है तो इसमें पीलापन रहता है। परंतु पकने पर छिलका कड़क हो जाता है। इसका मुख्य उपयोग चिप्स एवं पाउडर बनाने के लिये किया जाता है।

केले की उन्नत संकर प्रजातियां

(1) एच-1 (अग्निस्वार + पिसांग लिलिन)= यह लीफ स्पॉट फ्यूजेरियम बीमारी निरोधक कम अवधि वाली उपर्युक्त किस्म है। यह बरोइंग सूत्र कृमि के लिए अवरोधक है। इस संकर प्रजाति का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है और इसमें लगनेवाले बंच का वजन अमूमन 14 से 16 किलोग्राम का होता है। फल लम्बे, पकने पर सुनहरे या पीले रगं के हो जाते हैं। पकने पर इसमें हल्का खट्टा तथा मीठी खट्टी महक आती है। यह किस्म जड़ी फसल के लिये उपयुक्त है। तीन वर्ष के फसल चक्र में चार फसलें ली जा सकती हैं।

रोपण सामग्री (फसल उत्पादन तकनीक) = केला रोपण हेतु तलवारनुमा आकार के अतंभूस्तरीय जिनकी पत्तियां संकरी होती हैं, जिनको बीज के उपयोग मे लाया जाता है। तीन माह पुराना सकर्स जिसका वजन 700 ग्राम से 1 कि.ग्राम तक हो, रोपण के लिए उपर्युक्त होते हैं।

वर्तमान में केले के टिश्यूकल्चर पौधे व्यावसायिक रूप से उत्पादकों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं। क्योंकि इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीमारी रहित उत्तम गुणवत्ता वाले अधिक उत्पादक मातृ वृक्षों से उतक निकालकर प्रवर्धित किया जाता है। टिशु कल्चर पौधे टू-टू दि टाईप जिनोटाइप चयनित उतक को विट्रोंकल्चर पद्धति से वर्धित किया गया है। टिशु पौधों का स्वभाव दैहिक होता है और इसकी फसल एक साथ परिपक्व होती है। इसकी जड़ी (रेटून) से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।

भूमि की तैयारी एवं रोपण पद्धति = खेत की जुताई कर मिट्टी को भूरि-भूरि बना लेना चाहिये जिससे भूमि का जल निकास उचित रहें तथा कार्बनिक खाद ह्यूमस के रूप मे प्रचुर मात्रा में हो इसके लिये हरी खाद की फसल ले।

पौध अंन्तरालः कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखते हैं तथा पौधा रोपण के लिये 45 x 45 x 45 सें. मी. आकार के गड्डे खोदे प्रत्येक गडडे मे 12-15 किग्रा. अच्छी पकी हुई गोबर या कम्पोस्ट खाद रोपण के पूर्व साथ ही प्रत्येक गडडे में 5 ग्राम थिमेट दवा मिटटी में मिला दें।

बीज उपचार- प्रकंदों को उपचार के पूर्व साफ करें तथा जडों को प्रथक कर दें 1 प्रतिशत बोर्डो मिक्चर तैयार कर प्रकंदों को उपचारित करें इसके बाद 3-4 ग्राम बाबिस्टीन प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर प्रकंदों को 5 मिनट तक उपचार करें।

रोपण का समय:

1. मृग बहार (ग्रीष्म) अप्रैल से मई
2. कंदा बहार अक्टूबर

कांदा बहार की अपेक्षा मृग बहार की (ग्रीष्म) की फसल से अधिक उत्पादन मिलता है।

खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं देने की विधिः केले की फसल अपने पूरे जीवन चक्र में रोपण 5 - 7 माह के अन्दर प्रति पौधा नेत्रजन 200 ग्राम, स्फुर 40-50 ग्राम ओर पोटाश 250-300 ग्राम, कम्पोस्ट खाद 5 कि.ग्रा. एवं कपास या महुए की खली प्रति पौघा के हिसाब से दें। कम्पोस्ट खाद एवं फास्फोरस की पूर्ण मात्रा पौधा लगाते समय नत्रजन एवं पोटाश एक माह के अन्तराल से सात से आठ माह के अन्दर सात से आठ बार मे दें ।

अन्तरवर्तीय फसल

मृग बहारः इस फसल की रोपाई मई जून महीने में की जाती है। जिसमें केले के साथ , मूंग, भिण्डी, टमाटर, मिर्च, बैग़न इत्यादि फसले लें सकते हैं।

कांदा बहारः इस बहार के अन्तर्गत आलू, प्याज, टमाटर, धनियाँ, बैंग़न की फसलें ली जा सकती हैं।

केले की फसल में सस्य क्रियाएः केले की फसल में पौधों की जड़ों पर मिटटी चढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि केले की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं। इसलिये पौधों को सहारा देने के लिए मिटटी चढ़ाना जरूरी है। कभी कभी कंद बाहर आ जाते हैं। जिससे पौधे की वृध्दि रुक जाती है। इसलिए मिटटी चढ़ाना जरूरी है।

मल्चिंगः जमीन से जल वाष्पीकरण तथा खरपतवार द्वारा हास होता है। तथा भूमि से पोषक तत्व भी खरपतवारों द्वारा लिये जाते हैं। भूमि जल के वाष्पीकरण एवं खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्लास्टिक सीट पौधे की जड़ों के चारों ओर लगाने से उपरोक्त क्षति से बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त गन्ने के छिलके, सूखी घास, सूखी पत्तियॉ एवं गुड़ाई करने से जल हास कम हो जाता है। प्लास्टिक की काली पोलीथिन की मल्चिंग करने पर उत्पादकता में वृध्दि होती है।

अतंभूस्तरी (सकर्स) निकालनाः जब तक केले के पौधे में पुष्प गुच्छ न निकल पाएं तब तक सकर्स को नियमित रूप से काटते रहे। पुष्पण जब पूर्ण हो जावे तो एक सकर्स को रखा जाए तथा शेष को काटते रहे। यह ध्यान रखे कि एक वर्ष की अवधि तक एक पौधे के साथ एक सर्कस को ही बढ़ने दिया जाए वह जड़ी (रेटून) की फसल के रूप में उत्पादन देगा, बंच के निचले स्थान में जो नर मादा भाग है इस काटकर उसमें बोर्डोपेस्ट लगा दिया जाए।

सहारा देनाः जिन किस्मों में बंच का वजन काफी हो जाता है। तथा स्युडोस्टेंम के टूटने की संभावना रहती है। इसे बल्ली का सहारा देना चाहिए, केले के पत्ते से उसके डंठल को ढ़क दिया जाए।

पौधों को काटनाः केला बंच पुष्पण से 110 से 130 दिनों में काटने योग्य हो जाते हैं। बंच काटने के पश्चात पौधों को धीरे-धीरे काटें, क्योंकि इस क्रिया से मातृप्रकंद के पोषक तत्व जड़ी बाले पोधे को उपलब्ध होने लगते है। फसलस्वरूप उत्पादन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है।

जलप्रबंधनः केले की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते बड़े चौड़े होते हैं। एक पौधे के पत्तों का कुल क्षेत्रफल 50-60 वर्गमीटर होता है। इसलिए बड़े पैमाने पर पानी की वाष्पीकरण उत्सर्जन होने से केले को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। केले के पूर्ण वर्धित झाड़ों को प्रतिदिन 12-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ड्रिप पध्दति से सिचाई करने पर 60 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

फसल संरक्षण:

1 पनामा बिल्ट या उकठा रोगः यह बीमारी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के द्वारा फेलती है पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती है केले का पूरा तना फट जाता है प्रारंभ में पत्तियां किनारों से पीली पडती हैं प्रभावित पत्तियां डण्ठल से मुड़ जाती है प्रभावित पीली पत्तियां तने के चारों ओर स्कर्ट की तरह लटकती रहती है आधार पर (निचले भाग) तने का फटना बीमारी का प्रमुख लक्षण है। बैस्कूलर टिश्यू जड़ों और प्रकंद में पीले, लाल एवं भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते है पौधा कमजोर हो जाता है। जिसके कारण पुष्पन फलन नहीं होता है। इस बीमारी की फफूंद जमीन में अनुकूल तापक्रम, नमी एवं पी. एच. की स्थिति में लम्बी अवधि तक रहता है।

नियंत्रण:

1- गन्ना एवं सूरजमुखी के फसल चक्र को अपनाने से बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है।

2- सकर्स को लगाने के पूर्व 0.2 प्रतिशत बाबिस्टीन के धोल में 30 मिनट तक डुबोकर लगाना चाहिए।

3- ट्राइकोडर्मा बिरिडी जैविक फफूंद नाशक का उपयोग करना चाहिए।

4- जिलेटिन केप्सूल में 50 ग्राम बाबिस्टीन भरके केप्सूल अप्लीकेटर के सहारे कंद मे 45 डिग्री कोण पर रखने से बीमारी पर अच्छा नियंत्रण देखा गया है।

2. लीफ स्पाट (सिंगाटोका)- यह बीमारी स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसी फफूंद के कारण होती है। इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती हैं। क्योंकि टिशू हरे से भूरे रंग के हो जाते हैं। धीरे-धीरे पौधे सूखने लगते है। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे धब्बे दिखायी देते हैं। फिर यह पीले या हरी पीली धारियों में बदल जाते हैं। जो पत्तियों को दोनों सतहो पर दिखायी देते हैं अंत में यह धारियां भूरी एवं काली हो जाती हैं। धब्बों के बीच का भाग सूख जाता है।

नियंत्रणः प्रभावित सूखी पत्तियों को काटकर जला देना चाहिए। फफूंद नाशक दवाऐं जैसे डाइथेन एम-45, 1250 ग्राम /हेक्टेअर या बाबिस्टीन 500 ग्राम / हेक्टेयर या प्रोपीक्नोजोल 0.1 फीसदी का छिड़काव टिपॉल के साथ अक्टूबर माह से 3-4 छिड़काव 2-3 सप्ताह के अतंराल से करने से बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

3. एन्थ्रेक्नोजः यह बीमारी कोलेट्रोट्राईकम मुसे नामक फंफूद के कारण फैलती है। यह बीमारी केले के पौधे में बढ़वार के समय लगती है। इस बीमारी के लक्षण पौधो की पत्तियों, फूलों एवं फल के छिलके पर छोटे काले गोल धब्बों के रूप मे दिखाई देते हैं। इस बीमारी का प्रकोप जून से सितम्बर तक अधिक होता है क्योंकि इस समय तापक्रम ज्यादा रहता है।

नियत्रण:

1- प्रोक्लोराक्स 0.15 प्रतिशत या कार्वेन्डिज्म 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का धोल बनाकर छिड़काव करें।

2- केले को 3/4 परिपक्वता पर काटना चाहिये।

4 शीर्षगुच्छारोगः (बंचीटाप) = पत्तियों की भीतरी मिडरिब की द्वीतियक नसों के साथ अनियमित गहरी (मोर्सकोड) धारियां शुरू के लक्षण के रूप मे दिखाई देती हैं। ये असामान्य लक्षण गहरे रंग की रेखाओं मे एक इंच या ज्यादा लम्बे अनियमित किनारों के साथ होते हैं। पौधों का ऊपरी सिरा एक गुच्छे का रूप ले लेता है। पत्तियां छोटी व संकरी हो जाती हैं। किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। डंठल छोटे व पौधे बौने रह जाते हैं और फल नहीं लगते हैं। इस बीमारी के विषाणु का वाहक पेन्टोलोनिया नाइग्रोनरवोसा नामक माहू है।

नियत्रणः 1. रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।

2. रोग वाहक कीट नियंत्रण के लिये मेटामिस्टॉक्स 1.25 मि.ली. या डेमेक्रान 0.5 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

3. रोग रहित सकर्स का चुनाव करें।

5. केले का धारी विषाणु रोगः इस बीमारी के कारण प्रारंभ में पौधों की पत्तियों पर छोटे पीले धब्बे जो बाद में सुनहरी पीली धारियों मे बदल जाते हैं। क्लोरोटिक धारियां पत्तियों के लेमिना पर काला रूप लिये नेक्रोटिक हो जाती हैं। घेर का बहार न निकलना बहुत छोटी घेर निकलना एवं फलों में बीज का विकास प्रभावित पौधों के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग का विषाणु मिलीबग एवं प्लेनोकोकस सिट्री के द्वारा फैलाया जाता है।

नियंत्रणः प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये तथा मिलीबग के नियंत्रण के लिये कार्बोफ्यूरान की डेढ़ किलो ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में डालें।

कीट एवम् उनका नियंत्रणः

(1) केला प्रकंद छेदक (राइजोम बीबिल)- यह कीट केले के प्रकंद में छेद करता है। इसको इल्ली प्रकंद के अन्दर छेद करती है। परन्तु वह बाहर से नहीं दिखायी देती है। कभी-कभी केले के स्यूडोस्टेम में भी छेद कर देता है। इन छिद्रों में सड़न पैदा हो जाती है।

नियंत्रण - प्रकंदों को लगाने से पहले 0.5 फीसदी मोनोक्रोटोफास के धोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें। अत्याधिक प्रकोप होने पर 0.03 फीसदी फास्फोमिडान के घोल का छिड़काव करें।

(2) तना भेदकः तना भेदक कीट का मादा वयस्क पत्तियों के डंठलों में अण्डे देती है। जिससे इल्ली निकलकर पत्तियों एवं तने को खाती है। प्रारंभ में पौधे के तने से रस निकलता हुआ दिखायी देता है। फिर कीट की लार्वा द्वारा किये गये छिद्र से गंदा पदार्थ पत्तियों के डंठल पर बूंद-बूंद टपकता है जिससे तने के अन्दर निकल रहे पुष्प प्रोमोडिया शुष्क हो जाता है। इसका प्रकोप वर्ष भर होता है।

नियंत्रणः 1. मोनोक्रोटोफास की 150 मि.ली. मात्रा 350 मि.लीटर पानी मे घोलकर तने में इंजेक्ट करें।

2. घेर को काटने के बाद पौधों को जमीन से काटकर कीट नाशक दवा कार्वोरिल 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिडकाव करने से अंडे व कीट नष्ट हो जाते हैं।

(3) माहूः यह कीट केले की पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है। तथा बंचीटाप वायरस को फेलाने का प्रमुख वाहक है। इस माहू का रंग भूरा होता है। जो पत्तियों के निचले भाग या पौधे के शीर्ष भाग से रस चूसती है।

नियत्रणः फास्फोमिडान 0.03 फीसदी या मोनोक्रोटोफास 0.04 फीसदी के घोल का छिडकाव करें।

(4) थ्रिप्सः तीन प्रकार की थ्रिप्स केला फल (फिंगर) को नुकसान पहुंचाती है। थ्रिप्स प्रभावित फल भूरा बदरंग, काला तथा छोटे-छोटे आकार के आ जाते हैं। यदपि फल के गूदे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता पर इनका बाजार भाव ठीक नहीं मिलता।

नियंत्रणः मोनोक्रोटोफास 0.05 फीसदी का घोल बनाकर छिडकाव करें तथा मोटे कोरे कपड़े से बंच को ढंकने से भी कीट का प्रकोप कम होता है।

(5) लेस विंगस बगः यह कीट सभी केला उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। इस कीट से प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियों के निचले भाग में रहकर रस चूसती हैं। नियंत्रणः मोनोक्रोटोफास की 1.5 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।

(6) पत्ती खाने वाली इल्लीः इस कीट की इल्ली नये छोटे पौधों की बिना खुली पत्तियों को खाती है। पत्तियों मे नये छेद बना देती है।

नियंत्रणः थायोडान 35 ई. सी. का छिडकाव (1.5 मि. ली. प्रति लीटर पानी) पत्तियों पर करने से प्रभावी नियंत्रण देखा गया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अवैध कार्य के लिये मशहूर सुरत मनपा के कमिश्नर श्री क्या इस तरह की कार्यवाही सही हैं ?

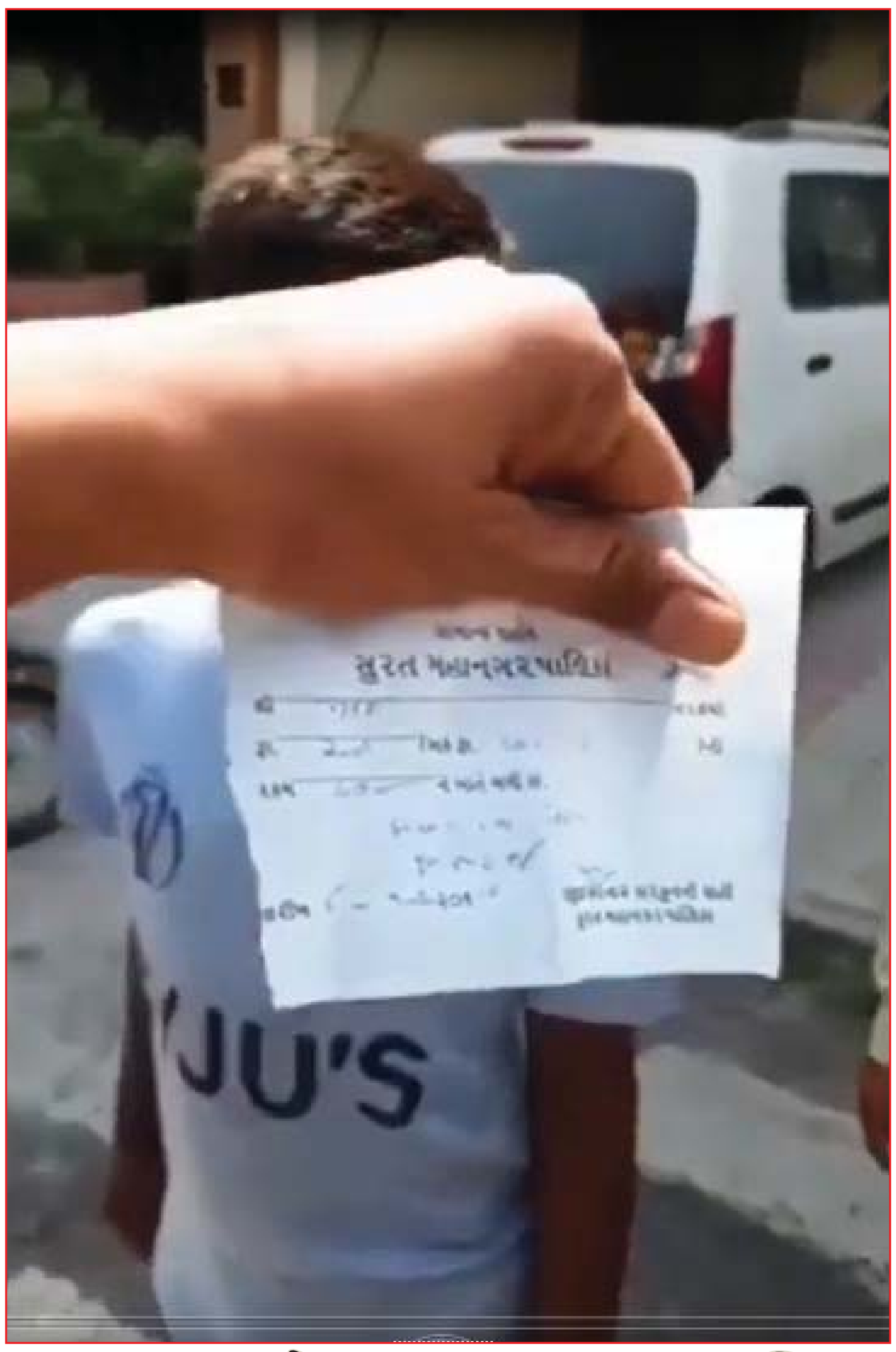

शोशल मीडिया में वायरल वीडियो हद कर दी आप ने S M C

मजदूरों पर दंड बिल्डर पर क्यों महेरबान सुरत मनपा

हद कर दी आपने एक नाबालिग बच्चे से भी वसूल लाये दंड सुरत मनपा

हनीट्रैप में फांस युवकों से रुपए ऐंठने वाला गिरोह कानून के शिकंजे में

राजकोट पुलिस ने हनीट्रैप में फांसकर युवकों से रुपए ऐंठने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया हैं।

पकड़े लोगों में एक दंपत्ति, जीआरडी के दो जवान समेत 5 लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष मारडिया नामक शख्स राजकोट में स्पा चलता है, जिसकी वजह से उसके पास काफी कोन्टेक्ट थें।

इन संपर्कों का उपयोग कर आशीष मारडिया अपनी पत्नी अल्पा मारडिया से युवकों को फोन कर अपने घर बुलाता थां।

युवक के पहुंचते ही आशीष मारडिया, जीआरडी के दो जवान समेत चार लोग वहां पहुंच जाते और युवक से डरा धमकाकर रुपए ऐंठ लेतें। कुछ दिन पहले अल्पा मारडिया ने मोरबी के एक शख्स को फोन किया और कहा कि मेरे पति घर में नहीं हैं, तुम जल्दी आ जाओं। अल्पा के फोन पर मोरबी का युवक उसके घर पहुंच गयां। युवक के अल्पा घर पहुंचते ही उसका पति आशीष मारडिया जी. आरडी के दो जवान जय परमार, शुभम शीशांगिया और रितेश फेकर के साथ वहां पहुंच गएं।

पुलिस की पहचान देकर देकर मोरबी के युवक से रु. 21500 ऐंठ लिएं।

बाद में रु. 200000 और मांगे जाने पर युवक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दीं।

जिसके आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर हनीट्रैप में फांसकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह के पांचों सदस्यों को गिरफ्तार पूछताछ शुरू की हैं।

12 वर्षीय किशोरी से तीन चचेरे भाइयों ने किया दुष्कर्म

नवसारी की खेरगाम में 12 वर्षीय किशोरे के साथ उसी के तीन चचेरे भाइयों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मासिक धर्म बंद होने पर उसकी जांच कराई गईं। जिसमें पता चला वह तीन महीने की गर्भवती हैं। नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के एक गांव में दंपत्ति 16, 12 और 10 साल की पुत्रियों के साथ रहत हैं।परिवार का मुखिया वलसाड की एक दुकान में नौकरी करता हैं।जबकि तीन पुत्रियों की माता अन्य घरों में काम करती है।पति शराब का आदी होने की वजह से घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी पत्नी ने निभाती है। पति–पत्नी के ज्यादातर समय बाहर होने की वजह से घर में केवल तीन बेटियां ही रहती हैं। जिसका फायदा उठाते हुए पड़ौस में रहनेवाले तीन चचेरे भाइयों ने 12 साल की बहन से दुष्कर्म किया।जब मौका मिलता तीनों भाई अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करते। किशोरी का मासिक धर्म बंद होने पर माता ने उसकी अस्पताल में जांच कराई। जांच की रिपोर्ट सामने आते ही माता के पेरों तले जमीन खिसक गई। 12 वर्षीय बेटी तीन महीने की गर्भवती थी। किशोरी की माता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता के तीन चचेरे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)